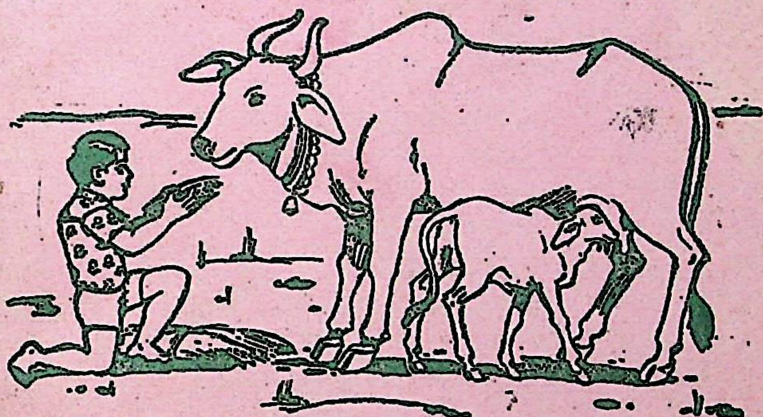
गावो विश्वस्य मातरः

१६६



गोग्रास

अ. भा. कृषि गोसेवा संघ
गोपुरी, वर्धा.

अनुक्रमणिका



संपादक : राधाकृष्ण बजाज, सहसंपादक : वसंत बोंबटकर

मुद्रक : रणजित् देसाई, परंधाम मुद्रणालय, पवनार जि. वर्धा, (महाराष्ट्र)

प्रकाशक : नारायण जाजू, मंत्री, अ. भा. कृषि-गोसेवा संघ, गोपुरी, वर्धा.

फोन : २८५२ तार : गोसेवा, गोपुरी, वर्धा– ४४२००१

पत्र-व्यवहार प्रकाशक के पते पर किया जाय ।

गोग्रास

वर्ष १४ : अंक १० गोपुरी, वर्धा गोग्रास योजना : वार्षिक २० रु.
११ अगस्त, ९० आजीवन २०० रु.

उत्तम खाद : कम्पोस्ट

—गांधीजी

[दिसम्बर १९४७ में बापू से समर्थन प्राप्त कर डॉ. राजेन्द्र-प्रसादजी की अध्यक्षता में मीराबहन ने एक अखिल भारतीय कम्पोस्ट परिषद आयोजित की थी। कम्पोस्ट के महत्व और उपयोगिता को ध्यान में रख कर इस परिषद ने कम्पोस्ट के उपयोग और प्रचार के देशव्यापी आंदोलन की सिफारिश की थी। परिषद की सिफारिशों पर गांधीजी ने निम्न प्रकार टिप्पणी की थी। —संपादक]

ये प्रस्ताव यदि केवल कागज पर ही नहीं रह गये, तो अच्छे और उपयोगी हैं। मुख्य बात यह है कि वे सारे भारत में कार्यरूप में परिणत किये जायं। ऐसा करने के लिए हमें कितनी ही मीराबहनों के साधनों का इस्तेमाल करना होगा। यदि भारत की जनता का स्वेच्छापूर्ण सहयोग इसे प्राप्त हो जाय, तो यह देश न केवल खाद्यान्न की कमी से ही मुक्त हो सकता है, बल्कि इससे देश को जरूरत से ज्यादा अन्न मिल सकता है। यह सेन्द्रिय खाद सदा मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करती है, उसे कमजोर नहीं बनाती, कमजोर नहीं होने देती। यदि नित्य रद्दी समझी जानेवाली चीजों को गड्ढे में डालकर सडा दिया जाय तो वह जमीन को फिर सुवर्ण खाद में प्राप्त हो सकती है और उससे करोडों रुपयों की बचत हो सकती है और निरन्तर वृद्धि करते हुए, अनाज-दालों आदि की उपज

कहीं अधिक बढा सकती है। इसके अलावा यदि रद्दी चीजों का उपयोग सोच-समझकर किया जाय तो आसपास की जगहें साफ रहेंगी। स्वच्छता न केवल देवत्व के तुरन्त बाद आती है, बल्कि वह स्वास्थ्य भी प्रदान करती है।

जानवर और मनुष्यों के मल-मूत्र को कचरे में मिलाकर सुनहरी खाद बनायी जा सकती है और यह बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। इसे डालने से जमीन की उर्वरक शक्ति बढ जाती है। इस खाद का निर्माण ही एक ग्रामोद्योग है। किन्तु अन्य ग्रामोद्योग की तरह यह भी तब तक ठोस परिणाम नहीं दिखाती, जब तक कि उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए सारे देश के करोडों लोग मिलकर उसे समृद्ध न बनायें।

कम्पोस्ट के प्रणेता सर एलबर्ट हावर्ड के विचार : हम मिट्टी की उर्वरता फिर से स्थापित और कायम रख सकते हैं और वह इस प्रकार कि हम प्रकृति के उस क्रियाकलाप का अनुसरण करें, जो हम सडकों के किनारे स्थित झाडियों और वन के किसी टुकडे में देख सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें अपने समूचे वानस्पतिक और जान्तविक जगत की रद्दी चीजों को गला-सडा कर समृद्ध खेती का साधन बना लेना होगा। वानस्पतिक और जान्तविक अवशेष मल-मूत्रमिश्रित ऐसी आदर्श खाद का निर्माण करते हैं कि उन्हें जीवाणु अंततः सुगन्धयुक्त "ह्यूमस" (सेन्द्रिय तत्व) बना देते हैं। इस प्रकार हमें सुन्दर वस्तुपाठ मिलता है और "ह्यूमस" की परिपूर्ण खाद बन जाती है। यह खाद डालकर हम अपनी जमीन की उर्वरक शक्ति कहीं अधिक बढा सकते हैं।

किन्तु हमारे बगीचों और खेतों में इतनी जगह नहीं होती है कि हम प्रकृति के क्रियाकलाप की झाडी और वन-निर्माण की नकल कर सकें, फिर भी गड्ढे की खाद के द्वारा हम ऐसे ही परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। एक वर्ष के बाद दूसरे वर्ष हम इस तरह की स्तरबद्ध कार्यवाही कर सकते हैं। चीनियों को, जो अधिक वेग से चीजों को सडाने की प्रक्रिया जानते थे और उधर अधिक ध्यान देते थे, पुरानी पद्धति से स्थान और समय दोनों की बचत होती थी। वे अपनी जमीन में "ह्यूमस" डालते थे, जो पौधों के लिए सबसे अच्छा खाद्य है, और इससे अपना बहुमूल्य समय भी बचाते थे, क्योंकि प्रकृति गड्ढे में कचरा सडाने में जितना समय लगाती थी, उसमें बचत हो जाती थी।

गाय की रक्षा करो
सबकी रक्षा हो जायगी

गोवंश-हत्या बंदी का केन्द्रीय कानून बनें

स्वराज्य-पूर्व के नेताओं ने भारतीय जनता को गोहत्या-बंदी का आश्वासन दिया था। लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वराज्य होते ही कलम की एक नोंक से गोहत्या वंद कर दी जायेगी। राष्ट्रपिता गांधीजी ने कहा था कि गोरक्षा में सबकी रक्षा है। गोहत्या होती है तो मुझे लगता है, मेरी हत्या होती है, गोरक्षा हिन्दू-धर्म की सारे विश्व को अमूल्य देन है।

नेताओं के वचनों के अनुसार स्वराज्य प्राप्त होते ही तीन महिनों के भीतर कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव नं. एफ २५-३/४७ के अनुसार ता. १९-११-१९४७ को सरकारी, विनसरकारी विशेषज्ञों की एक समिति भारत सरकार के पशुपालन प्रमुख सरदार दातारसिंगजी की अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी। उस समिति ने एक साल के भीतर ता. ६-११-४८ को सर्वसम्मत सिफारिश की कि दो वर्ष के भीतर गोवंश की हत्या परिपूर्ण वंद करने के लिये केन्द्रीय कानून बनाया जाय। कानून बनाने में दो वर्ष से अधिक समय न लगें। इन दो वर्षों में गोसदनों के लिये स्थान की व्यवस्था की जाय। फंडस् के लिये गोशाला सेस, लागबाग, वित्ती, कटौती, धर्मादा आदि को कानूनी मान्यता दी जाय और इस फंड का उपयोग गोशाला – गोसदनों के विकास के लिये किया जाय। इन सिफारिशों के अनुसार भारतीय संविधान के मार्गदर्शक तत्त्वों में गोरक्षार्थ कलम ४८ जोडी गई। खेद है कि कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई अमल नहीं किया।

पिछले हजारों वर्षों से सभी भाषाओं के सभी कोषों में 'गाय' शब्द में गाय-बैल, नर-मादा, दोनों का समावेश होता रहा है। दुर्भाग्य

से १९५८ में सुप्रीम कोर्ट ने बैल को गाय से अलग, बूढे बैलों के कतल की इजाजत दे दी । यह कहकर की मांस बेचना कुछ लोगों का बुनियादी अधिकार है! संविधान संशोधन नं. २५, १९७२ द्वारा संविधान में यह दुरुस्ती की गई कि मांस बेचना किसीका फंडामेंटल राईट नहीं हो सकता ।

१९६६ में जगत्गुरु शंकराचार्यजी पुरीवालों ने गोरक्षार्थं ७३ दिन के उपवास किये थे । वहुत वडा आंदोलन हुआ था । उस समय वतौर समझौते के भारत सरकार ने गौ-सुरक्षा समिति वनाई थी । उस समिति ने सात वर्ष के विचारविनिमय के वाद ता. १७-९-१९७३ को सर्वसम्मत निर्णय दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की मर्यादा में भारत सरकार अविलंव कानून वनायें । वनवावें / उनका समुचित अमल करें / करवावें । इंदिरा सरकार ने समझौते के इस निर्णय पर कोई अमल नहीं किया । स्पष्ट रूप से वचन भंग किया ।

१९७६ में संत विनोवाजी ने गोरक्षार्थ आमरण अनशन का संकल्प किया था । उस समय वतौर समझौते के इंदिरा सरकार ने सारे देश में गोहत्या-बंदी कानून वनवाने का आश्वासन दिया था । इस वचन के अनुसार आंध्र, महाराष्ट्र, आसाम और तामिलनाडु में गोहत्या-बंदी कानून वने । अनेक प्रदेशों में पहले ही गोहत्या-बंदी कानून थे । केरल और बंगाल में कानून वनने रह गये ।

जनता सरकार के आने पर गोहत्या-वंदी के लिये अनेक प्रयास किये गये । विपक्ष के सभी नेता पू. विनोवाजी से वर्धा आकर मिल गये । कांग्रेस महासमिति ने ता. ८-४-७९ को प्रस्ताव करके भारत सरकार से अनुरोध किया कि आचार्य विनोवाजी की मांग के अनुसार गोहत्या-वंदी कानून वनाया जाय । डॉ. रामजी सिंग ने लोकसभा में प्रस्ताव रखा था कि भारत सरकार गोहत्या-वंदी कानून वनावें । यह प्रस्ताव ता. १२-४-७९ की लोकसभा ने पारित किया था । सारे प्रयासों के वाद भी सफलता नहीं मिली, तव संत विनोवाजी

ने ता. २१-४-७९ को आमरण अनशन आरंभ किया। पांच दिन के उपवास के वाद समझौता हुआ। ता. २६-४-७९ को प्रधानमंत्री श्री. मोरारजी देसाई ने पार्लमेन्ट में वयान देकर संत विनोवाजी की मांग एक साल के भीतर पूरी करने का वचन दिया।

१९८० में फिर से इंदिरा-सरकार आई। उन्हें पिछले वचनों का स्मरण दिलाया गया। प्रधानमंत्री इंदिराजी अनेक वार संत विनोवाजी से मिली थीं। लेकिन १९८१ तक जव गोहत्या-वंदी कानून नहीं वना, सरकार ने अपने वचनों का पालन नहीं किया, यह देखकर ११ जनवरी १९८२ से संत विनोवाजी ने अपने आश्रमवासियों द्वारा मुंवई के देवनार कतलखाने पर सत्याग्रह शुरू करवाया, जो आज ९ साल से अखंड चल रहा है।

अधिकांश प्रदेशों के गोहत्या-वंदी कानूनों में वूढे वैलों के कतल की छूट होने के कारण वूढे वैल के नाम पर जवान गाय-वैल रात-दिन कट रहे हैं, यह देखकर पू. विनोवाजी ने संपूर्ण गोवंशहत्या-वंदी की अपनी मूल मांग पर जोर देना तय किया। और मांग रखी कि कृषिप्रधान भारत में किसी भी उम्र के गाय-वैल की हत्या न हो, इसलिए गोवंश-हत्या वंदी का केन्द्रीय कानून अविलंव वनाया जाय।

गोहत्या को बढावा देनेवाले एक्सपोर्टस् पर बंदी

सन् १९७५ के पूर्व मांस का निर्यात नहीं होता था। १९७७ में २००० टन मांस का निर्यात हुआ। वह आज १ लाख टन से भी अधिक निर्यात हो रहा है। विदेशों में मांस के भाव १० गुने अधिक हैं। यहां गोमांस का भाव जव १० रु. किलो था, तव विदेशों में १०० रुपये किलो से भी अधिक भाव था। इस कारण जिंदी गाय की अपेक्षा मारी गाय अधिक लाभदायी होती है। मांस-निर्यात वंद होने से कतल का वडा प्रलोभन खतम होगा।

यही वात चमडे की है। गाय-भैंस के चमडे का निर्यात वंद किया जाने से कतल का दूसरा प्रलोभन कम होगा। स्वाभाविक मृत्यु

का चमडा गांवों में अधिक रहेगा। उससे करोडों लोगों को रोजगार मिलेगा।

पशु-खाद्यों में खली आदि का निर्यात होता है। उसको बंद कर के वह खली भारतीय पशुओं को खिलाई जावेगी तो विदेशी विनिमय-प्राप्ति के मुकावले वहुत अधिक लाभ होगा। गायों का दूध वढेगा, वैलों की कार्यक्षमता वढेगी। गोवर-गोमूत्र से ऊर्जा-विजली मिलेगी और भूमि को उत्तम खाद मिलेगा। सव तरह से देश का भला होगा।

अ. भा. कृषि गोसेवा संघ
गोपुरी – वर्धा (महाराष्ट्र)

राधाकृष्ण बजाज
अध्यक्ष

अन्न-वस्त्र उद्योगों पर नियंत्रण, ग्रामोद्योगों का प्रसार

भारत में सवसे वडी समस्या है वेकारी की, रोजी-रोटी की। इस समस्या का समाधान यंत्रोद्योगों से संभव नहीं। यंत्र पांच सौ लोगों को काम देते हैं, तो पांच हजार को वेकार वनाते हैं! इस समस्या के हल के लिए आवश्यक है कि अन्न, वस्त्र से संबंधित वडे उद्योगों पर, नियंत्रण लगाया जाय। जो काम पशु-शक्ति एवं मानव-शक्ति से संभव है, उन कामों में पावर-यंत्रों का दखल वंद किया जाय। मनुष्य-चालित एवं पशु-चालित यंत्रों को अधिक से अधिक वढाया जाय। विज्ञान की मदद मिलेगी तो ऐसे यंत्रों में वहुत अधिक प्रगति हो सकेगी। जैसे, साधे चरखे की जगह अंबर चरखा निकलने से छह गुनी कताई होने लगी है।

ग्रामोद्योगों को वढावा किस प्रकार दिया जाय, इस संबंध में प्रमुख उद्योगों के नाम नीचे दिये हैं। छोटे-वडे सैकडों उद्योग ग्रामों में चल सकते हैं।

१. रासायनिक खादों पर पाबंदी लगाई जाय एवं कंपोस्ट खाद का प्रचार किया जाय, तो करोडों लोगों को घर बैठे काम मिलेगा।
२. चमडे का निर्यात बंद किया जायेगा तो करोडों लोगों को अपने ही गांव में उद्योग-धंदा मिलेगा।
३. वस्त्रोद्योगों पर नियंत्रण किया गया तो हाथ-कताई, हाथबुनाई के जरिये करोडों लोगों को घरबैठे काम मिलेगा।
४. शक्कर उद्योग को नियंत्रित किया जाय तो लाखों लोगों को अपने ही गांव में गुड बनाने का धंदा मिलेगा, स्वास्थ्यकर खाद्य मिलेगा।
५. तेल उद्योग को नियंत्रित किया गया तो लाखों लोगों को अपने ही गांव में काम मिलेगा, स्वास्थ्यकर ताजा तेल मिलेगा। पशुओं को खली मिलेगी, दूध बढेगा तेल का परिवहन बचेगा।
६. धान-पॉलिसिंग की मिलों पर नियंत्रण किया गयातो लाखों लोगों को घरबैठे धान-कुटाई का काम मिलेगा।
७. दूध-घी का उत्पादन बढाया जाय। उनका केन्द्रीयकरण रोका जाय, तो करोडों लोगों को स्वास्थ्यकर खाद्य मिलेगा। हर घर में दूध या मठ्ठा जरूर मिलेगा।
८. बडे कारखानों द्वारा फलों के पेय बनाने की अपेक्षा ग्रामोद्योगों द्वारा वह काम करने से गांवों के प्रचूर फलों को नष्ट होने से बचाया जा सकेगा। गांवोंमें उद्योग मिलेगा।
९. खेती में ट्रॅक्टर को नियंत्रित रखें, जिससे बैलों को सालभर पूरा काम मिलेगा। भूमि का क्षरण कम होगा। डिझेल बचेगा, प्रदूषण कम होगा।
१०. ट्रक द्वारा परिवहन २५-३० किलोमीटर के भीतर रोका जाकर सुधरी बैलगाडी का प्रचलन बढाया जाय। इससे करोडों आदमी और बैलों को काम मिलेगा। ट्रॅक्टर, ट्रक को नियंत्रित करने से पेट्रोल, डिझेल में बचत होगी, प्रदूषण कम होगा। विदेशी विनिमय बचेगा।

कंपोस्ट खाद के लाभ

रासायनिक खाद की तुलना में कंपोस्ट खाद से शुरू के कुछ वर्षों में फसल कम होगी, थोडी हानि भी उठानी पडेगी, लेकिन दो साल वाद भूमि की उर्वरा शक्ति वढने लगेगी। पांच-सात साल वाद खासी अच्छी फसल मिलने लगेगी।

वर्धा के पास भीडी गांव में, श्री अरविन्द आश्रम के ग्लोरिया फॉर्म में, क्वेकर सेंटर रसुलिया होशंगावादमें, कस्तुरवाग्राम कृषि-क्षेत्र इंदौर (म. प्र.) में, डहाणू (महाराष्ट्र) के फलवागों में, वृन्दावन में स्वामी अखंडानंदजी आश्रम में, संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारीजी की संस्था में और अन्य कई जगह दस-पंद्रह सालों से रासायनिक खाद एवं कीटनाशक उपयोग में नहीं ला रहे हैं। फिर भी उनका दावा है कि रासायनिक खेती करनेवालों की तुलना में उनकी आमदनी कम नहीं हैं। रासायनिक खाद का परित्याग करने से उनकी प्रारंभिक लागत वहुत कम हुई हैं। साहुकार से कर्जा नहीं लेना पडता। वर्षा कम-अधिक हुई तव भी रासायनिक खेती की तुलना में नुकसान कम होता है। रासायनिक खाद खरीदते थे, तव कर्जे में डूबे रहते थे।

रासायनिक खाद से भूमि धीरे-धीरे कमजोर पडने लगती है। इससे सालाना रासायनिक खाद की मात्रा वढानी पडती है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में ५५ गांवों में केले की खेती का सर्वे करने पर पाया गया कि प्रारंभ में जहां एक पेड को २५ ग्राम रासायनिक खाद देने से जितनी फसल होती थी वहां पंद्रह साल वाद अव पांच गुना याने १२५ ग्रॅम खाद देने पर भी आधी भी फसल नहीं मिलती है। केले जल्दी सडने लगते हैं, मिठास भी पहले जैसी नहीं हैं।

गोवर-गोमूत्र से वनाये कंपोस्ट खाद से भूमि की उर्वरा शक्ति साल-दरसाल वढती है। इस कारण आगामी सालों में खाद की मात्रा कम देने से भी काम चल जाता है। रासायनिक खाद लगातार पंद्रह साल इस्तेमाल करने से जवान भूमि भी बूढी होकर मरने के रास्ते लग जायेगी! जैसे, लुधियाना जिले में हो रहा है। यदि कंपोस्ट खाद लगातार १५ साल दिया जाय तो वूढी भूमि भी जवान होकर उत्तम फसल देने लगेगी। जैसे, पांदेचरी, इंदौर आदि में हो रहा है।

रासायनिक खाद से अन्न, जल, भूमि में सूक्ष्म जहर फैलता है। जमीन को उर्वरा वनानेवाले केंचुओं जैसे जीव मरते है। रासायनिक खादों के साथ कीटनाशकों का इस्तेमाल लाजमी होने से फसलों के विघातक जंतु अवश्य मरते हैं, पर साथ ही पोषक जंतुओं का भी विनाश होता है। कीटनाशकों का केवल १०% हिस्सा कीटनाशन के कामों में आता है, वाकी ९०% हिस्सा हवा व भूमि में जाकर पानी आदि में जहर फैलता है। कीटनाशकों से जितना लाभ होता है, उससे दस गुना हानि होती है! भोपाल जैसे गैस-कांडों में हजारों की मौत और लाखों में वीमारि यां फैली हैं। इन कीटनाशकों को तुरंत वंद करके मानव-जीवन की रक्षा करनी चाहिए। जहरीले कीटनाशकों के स्थान पर करंजी की खली, गोमूत्र, नीम आदि से कीटनाशक तैयार किये जा सकते हैं। ऐसे भी प्रयोग हुए हैं कि भूमि में खुद-व-खुद पोषक जीव तैयार हो, जो कीटनाशकों का मुकावला कर सकें।

भारत रासायनिक खादों को वढा रहा है और विदेशों में कीटनाशकों पर पावंदी लगाई जा रही है। एवं कंपोस्ट खाद को वढावा दिया जा रहा है। कंपोस्ट खाद से तैयार फसलों के हेल्थ फुड सेंटर के नाम से स्वतंत्र वाजार चलते हैं और लोग उन्हें दुगुनी

कीमत देकर ख़रीदते हैं। कंपोस्ट खाद से पैदा होनेवाला अनाज, साग-सब्जी सूक्ष्म जहर से मुक्त होते हैं एवं सुस्वादु, पोषक और टिकाऊ होते हैं।

कंपोस्ट खाद में कुडा-करकट, मल-मूत्र, पान-पत्ती, सभी का इस्तेमाल होने के कारण गांव-नगर स्वच्छ, साफ-सुथरे रहेंगे, लोगों का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। करोडों लोगों को अपने ही गांवों में रोजगार मिलेगा। दरिद्र-रेखा से नीचेवालों को ऊपर उठाया जा सकेगा एवं पर्यावरण शुद्ध होगा।

कंपोस्ट खाद का सही मूल्य मालुम होने पर हर किसान, बूढे अनउपजाऊ पशुओं को अवश्य संभालेगा। उन्हें खिलाये गये चारे की कीमत से खाद की कीमत अधिक होगी। बूढे पशु किसान के लिये भाररूप नहीं होंगे। करोडों गायों की रक्षा विना किसी सरकारी खर्चे के सहज भाव से हो सकेगी। कंपोस्ट खाद से अनुपयोगी पशुओं को जीवन-दान मिलेगा। हमारे पास कृषि-योग्य ४८ करोड एकड भूमि है। उसको पर्याप्त खाद देना हो तो आज से दुगने-तिगने पशु वढाने होंगे। बूढे पशु भी भूमि पर भार न होकर भूमि को मददगार होंगे। कंपोस्ट खाद से भूमि की रक्षा होगी, गायों की रक्षा होगी, मानवों की रक्षा होगी एवं पर्यावरण शुद्ध होगा।

रासायनिक खादों के लिये सालाना करीव ४ हजार करोड की सवसीडी दी जा रही है, वह तुरंत वंद होनी चाहिए। हजारों करोड खर्च करके विदेशों से रासायनिक खाद मंगाये जा रहे हैं। उनकी आयात रोकनी चाहिये। दोनों तरह से देश का पैसा वचाना चाहिये। पैसा खर्च करके पर्यावरण में जहर फैलाना भूमि की उर्वरा शक्ति कम करना, किसी भी हालत, में राष्ट्र के लिये भलाई की वात नहीं हो सकती।

लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और नेहरू-सरकार ने सरदार दातारसिंग कमेटी के रूप में राष्ट्र को गोहत्या-बंदी एवं गोरक्षा का जो वचन दिया है उसे निभाने की भारत सरकार की जिम्मेवारी हैं। जब तक इस देश में गाय-बैलों का खून गिरता रहेगा तब तक देश में शांति नहीं हो सकती गोहत्या के एवं वचनभंग के महत्पातक से देश जलता रहेगा।

तिलक पुण्यतिथि १-८-९०
अ. भा. कृषि गोसेवा संघ,
गोपुरी-वर्धा (महाराष्ट्र)

राधाकृष्ण बजाज
अध्यक्ष

जीत हिंदी की

प्रसिद्ध गांधीवादी नेता और कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष डा. पट्टाभी सीतारामैया अपने सभी मित्रों को पत्र लिखते, तो हिंदी में ही पत्ता लिखते थे।

इस वजह से दक्षिण के डाकखाने वालों को बड़ी असुविधा होती थी। उन सबने कहला भेजा कि आप अंग्रेजी में पते लिखा करें, ताकि इसे बांटने में आसानी हो।

डा. सीतारामैया ने उनसे कहा – भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, अतः मैं अपने पत्रव्यवहार में उसीका प्रयोग करूंगा।

पोस्ट आफिस वालों ने उन्हें धमकी दी कि यदि आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आयेंगे, तो हम आपकी सारी चिट्ठियां डेड लेटर आफिस को भेज देंगे!

डा. सीतारामैया पर इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। दोनों के बीच अर्से तक शीत युद्ध जारी रहा।

अंत में डाकखाने वाले ही झुक गये। अंततः उन्हें मछलीपट्टनम् के डाकघर में एक हिंदी जाननेवाले आदमी को रखना ही पडा। इस तरह जीत हिंदी की ही हुई।

हमारे जीवन में 'गांधी' को दाखिल करें

कुछ मित्रों ने सुझाया है कि हम 'गांधी' का नाम लेकर अभियान चलाने जा रहे हैं, तो पहले अपनी और अपनी संस्थाओं के बारे में जरा आत्मनिरीक्षण कर लें कि हमारा काम गांधी-विचार से कितना दूर चला गया है ? अगर ऐसा हो, तो हम किस मुंह से और कौनसा वैचारिक आधार लेकर जनता को गांधी की चुनौती का आभास करायेंगे ? वास्तव में गांधी की चुनौती तो सबसे पहले हमीं लोगों के लिए है, जो गांधी का संदेश लेकर लोगों के पास जाना चाहते हैं। अतः लोगों के पास जाने से पहले यह उचित ही होगा कि हम लोग अपना और अपनी प्रवृत्तियों का कुछ आत्मनिरीक्षण करें। अपने में और अपने कामों में जहां "गांधी" न दिखे वहां उसे दाखिल करें। इसके लिये व्यक्तिगत और सामूहिक संकल्प करें। उदाहरण के लिए, हम ग्रामस्वराज्य, ग्राम-स्वावलंबन और यंत्रोद्योग से मुक्ति की बात लोगों से कैसे कहेंगे, जब तक हम खुद ग्रामोद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनेवाली कारखानों की चीजों का संकल्पपूर्वक बहिष्कार न किये हुए होंगे ? इसी प्रकार सामूहिक क्षेत्र में भी हमारी संस्थाओं के कामों में जो दोष आ गये हैं, उन्हें योजनापूर्वक और संकल्पपूर्वक निकालने की शुरूआत हमें करनी होगी। अतः नवंबर से पहले, क्या हम व्यक्तिगत भी और सामूहिक रूप से भी कुछ संकल्प लेकर शुद्धि की प्रक्रिया को शुरू करेंगे ? ऐसा हुआ तो हम आत्मविश्वास और तेजयुक्त होकर लोगों के सामने जा सकेंगे। संपूर्ण क्रांति आन्दोलन के दिनों में जयप्रकाशजी ने "लाइसेंस रिन्यू" कराने की बात कही थी, वह हमें याद होगी।

संकल्प छोटा ही क्यों न हो, उसमें शक्ति अपार होती है। जयप्रकाश और विनोबा का तो सारा जीवन क्रांति के लिये समर्पित था। उन्हें किसी नये संकल्प की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन १९५४ में बोधगया के सर्वोदय सम्मेलन में जब अचानक जयप्रकाश के मुंह से "जीवन-दान" का शब्द निकला, वहां एक बिजली की-सी लहर दौड गई, जिसकी प्रतिक्रिया महिनों और वर्षों तक देशभर में होती रही। उस छोटी-सी घटना ने सर्वोदय आन्दोलन को उस समय मानों झकझोर दिया था।

इसी तरह क्या नवंबर में होने वाले गांधी-चुनौती अभियान के पहले "लाइसेंस रिन्यू" कराने की कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती ? होनी चाहिये !

– सिद्धराज ढड्ढा

खादी-संस्थाओं से नम्र निवेदन

१. आर्थिक शोषण से देश को बचाना है।
२. आरामतलबी मां-बापों से छुट्टी पाना है।
३. नवयुवकों को भावी विनाश का भान कराना है।
४. दरिद्र-रेखा से नीचेवालों को उठाना है।

१. आज देश में अनेक प्रकार से आर्थिक शोषण हो रहा है। भारत को राजनैतिक गुलाम बनाने की शुरूआत इस्ट इंडिया कंपनी से हुई थी, उसी प्रकार इन दिनों मल्टीनेशनल कंपनियों का भारत को आर्थिक गुलाम बनाने के लिये आक्रमण आरंभ हुआ है। इसे समय रहते रोकना आवश्यक है।

भारत में उद्योगीकरण से विकास करने का प्रयास पिछले ४० सालों से बराबर चल रहा है। इस उद्योगीकरण के पीछे देश कर्जदार बन गया है। उद्योगीकरण का परिणाम यह हुआ कि अमीर, अमीर होता गया और गरीब, गरीब हो रहा है! विकास की इस नीति के आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

२. आज के आरामतलबी माय-बाप सरकार के शिकंजे में देश फंसा है। जो सरकार २३ करोड लोगों की आमदनी साठ रुपये मासिक से कम बताती है, वही सरकार हजारों की तनख्वाह पानेवाले सत्ताधीश, सांसद अपना और अपने साथी, नौकरशाही, शिक्षक, डॉक्टर आदि का वेतन, भत्ता रोज-रोज बढाते जा रहे हैं। क्या कोई भी मां-बाप अपने बच्चों को भूखा रखकर माल-मलीदा उडायेंगे? इन आरामतलबी मां-बापों के शिकंजे से छुट्टी पाये बिना गीत नहीं।

देश का निर्माण उन त्यागी-तपस्वी मनीषियों ने किया था, जो लंगोटी लगाकर भिक्षा पर जीते थे, देश का एक पैसा भी खर्च करना हराम समझते थे। आज आवश्यकता है, ऐसे मां-बापों की जो खुद भूखे रहकर भी बच्चों का पेट भरें। देश को निःस्वार्थी, निष्पक्ष सेवकों की सेना चाहिए, जो दरिद्र-रेखा के नीचेवालों को पेटभर रोटी खिला सकें। बेकारी भत्ता देश को भिखारी बनायेगा। जरूरत है रोजगार देने की, ताकि सम्मान की रोटी खा सकें।

३. हमारे नौजवान आज अंधेरे में हैं। उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकती जा रही है, इसका उन्हें भान नहीं है। देश के कर्णधार सत्ता-संपत्तिवालों ने जाने-अनजाने देश को इस तरह एक्सप्लाइट किया है कि

नवजवानों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। कर्जा लेकर उसका मजा बुजुर्गों ने लूटा है और कर्ज चुकाने व व्याज देने का भार नवजवानों के मत्थे आनेवाला है। केमिकल फर्टिलायझसरों से अधिक उत्पादन का लाभ बुजुर्गों ने उठाया है और इन खादों से उत्पादन-शक्ति घटी हुई भूमि जवानों के भाग्य में आनेवाली है। विदेशों में कहावत है – "Fertilizers are better for fathers and worst for sons."

भूमि में से कोयला, तेल गॅस आदि निकालते जा रहे हैं। जब तक जवान बडे होंगे, यह सारी भूमि खनिजविहीन हो जायगी। आज की पीढी ने उत्तम अन्न खाया, शुद्ध जल पिया और ताजा हवा ली। अब नवजवानों की भावी पीढी के लिये जहर-मिश्रित अन्न, प्रदूषित जल और अशुद्ध हवा मिलेगी। इन कल-कारखानों ने सभी नदियों का जल प्रदूषित कर दिया। इनकी कमाल देखिये कि गंगा का जल भी शुद्ध नहीं रहने दिया। नवयुवकों को अपने भावी विनाश का भान कराना आवश्यक है। नवजवानों को सही स्थिति समझेगी तो रास्ता खोजने की शक्ति उनमें हैं।

४. साठ रू. मासिक से कम आमदनीवाले दरिद्र-रेखा के नीचे २३ करोड लोग हैं, ऐसा पार्लमेन्ट में प्रधान मंत्रीजी ने कहा है। आज की स्थिति को देखते हुए दोनों समय पेटभर रोटी-कपडा मिलने के लिये प्रति व्यक्ति १५० रु. मासिक से कम आमदनीवाले दरिद्र-रेखा के नीचे मानने चाहिए।

(अ) स्वराज्य के पूर्व खादी ने जो त्याग-तपस्या की थी, उसको दोहराने का समय आया है। राजनैतिक स्वतंत्रता के लिये जो त्याग-तपस्या की थी, वही अब आर्थिक स्वतंत्रता के लिये करनी होगी। सेवाग्राम के खादी-संमेलन में मुझे विचार रखने का मौका मिला था। खादी मिशन ने एक करोड लोगों को काम देने की जो योजना बनाई है, प्राथमिक शुरूआत के तौर पर योजना से पूरा संतोष है। इसमें सिर्फ एक ही बात कहनी है कि इन एक करोड लोगों में कम से कम ६०% याने साठ लाख दरिद्र-रेखा के नीचे वालों को काम दिया जाय।

(आ) खादी-संस्थाओं का लक्ष्य अधिक-से-अधिक रुपयों का उत्पादन करने का है, उसकी जगह लक्ष्य अधिक-से-अधिक रोजगार देने का होना चाहिए। कितने लोगों को काम दिया, दरिद्र-रेखा के नीचेवाले कितनों का उठाया, इस पर काम की प्रगति एवं विकास आंका जाना चाहिए।

(इ) देश की आज की स्थिति का सही चित्र सभी ग्रामवासियों के, नवयुवकों के एवं आम प्रजा के सामने रखकर विचार-प्रचार करना चाहिए। जनता के सामने सही चित्र रखना, इतना तो हम कर ही सकते हैं।

(ई) संस्थाओं को चाहिए कि सेन्सस रिपोर्ट पर से यह पता लगायें कि दरिद्र-रेखा के नीचेवाले लोग किस क्षेत्र में कितने हैं। वहां जाकर स्थिति देखी जाय। सब लोगों से मिलकर योजना बनाई जाय कि सबको रोजी-रोटी किस प्रकार मिल सकेगी। ऐसी योजनाएं बनाकर जिला कलेक्टर और प्रदेश सरकारों को भेजी जानी चाहिए। अखबारों में प्रसारित की जानी चाहिए। यह रचनात्मक काम हमारी संस्थाएं अवश्य कर सकती हैं। गांधी की संस्थाओं में ८०% कार्यकर्ता खादी-क्षेत्र में होने के कारण खादी-संस्थाओं की जिम्मेवारी विशेष रूप से है। ऐसी योजनाओं को सरकार से मंजूर जनता के डेप्युटेशन भी कलेक्टर के पास ले जाये जा सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता उनमें प्रेरक रहें, अगवानी करें।

(उ) सरकार दरिद्र-रेखा के नीचेवालों को रोजी-रोटी देने की बात ईमानदारी से सोचेगी तो उसे खादी-ग्रामोद्योग और खेती-गोपालन का ही आधार लेना पडेगा। ऐसी स्थिति में सरकार कह सकती है कि जितनी चाहिए पूंजी और सबसीडी देंगे, खादीवाले सबको काम दें। उस स्थिति में हमको हिम्मतपूर्वक कहना चाहिए कि अवश्य काम देंगे। हमें सबसीडी नहीं चाहिए, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। सूत एवं खादी-बिक्री की जिम्मेवारी सरकार उठाये। कानूनी एवं तकनीकी दिक्कतें दूर करें।

(ऊ) खादी मिशन ने एक करोड लोगों को काम देने की योजना बनाई है, उसके लिये भी प्रोटेक्शन की मांग करनी होगी। उसके बिना योजना सफल होना आसान नहीं, मेरा विश्वास है कि दरिद्र-रेखा के नीचेवालों को उठाने के लिये जो प्रयास किये जायेंगे, उसी में से देश के लिये सही विकास की योजना भी हाथ लगेगी।

अ. भा. कृषि गोसेवा संघ,
गोपुरी-वर्धा (महाराष्ट्र)
१० जुलाई, १९९०

राधाकृष्ण बजाज
अध्यक्ष

संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ निश्चयः ।
मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः

सदा संतुष्ट जो योगी संयमी दृढ-निश्चयी ।
अर्पी मज मनो-बुद्धि भक्त तो आवडे मज ॥ १२ : १४

पू. दादाभाई नाईक

[हमारे सहयोगी मित्र श्री दादाभाई नाईक की ९०वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उनका हार्दिक अभिनंदन ! जीवेत शरदः शतम् ! – संपादक]

१५ अगस्त १९५१ के राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर कुष्ठधाम, दत्तपुर में राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए निमंत्रण देने जब मैं सेवाग्राम गया तब वह मेरी पहली मुलाकात श्री दादाभाई नाईक के साथ हुई। वे खादी के काम से सेवाग्राम आये हुए थे, और पू. श्री. श्रीकृष्णदासजी जाजू, जो महारोगी सेवा मंडल, दत्तपुर के अध्यक्ष थे, उनके यहां ही आपसे भेंट हुई। पू. जाजूजी के सुझाव पर दादाभाई ने तुरंत निमंत्रण स्वीकार किया और अगले दिन दत्तपुर पधारे। उस समय गांधी-टोपी, धोती, कुर्ता, एकहरी लंबी शरीरयष्टि और "क्लिन-शेव", छोटी-छोटी मुंछें, ऐसा सरल व्यक्तित्व आज भी मैं भूला नहीं। आगे दत्तपुर में उनके अनेक व्याख्यान तथा गीता आदि पर प्रवचन हुए। लेकिन वह मेरे लिए प्रथम व्याख्यान उनके राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की जीती-जागती तस्वीर प्रस्तुत करनेवाला था। आजादी के लिए लाखों लोगों ने जो त्याग, कष्ट, कारावास की यातनायें, संपत्ति, घर, नौकरी आदि के नुकसान हंसते-हंसते उत्साहपूर्वक सहन किये, वे सब थोडे में एक भुक्त-भोगी से सुनने को मिले। दादाभाई ग्रँड मेडीकल कॉलेज, बंबई के तृतीय वर्ष में पढते थे। गांधी के आवाहन पर कॉलेज छोड दिया। पू. मनोहरजी दिवाण से उनकी गहरी मित्रता थी ही। दिनभर काफी स्नेह से दत्तपुर में बिताकर वापस सेवाग्राम गये।

पू. दादाभाई के परिवार से परिचय का कारण हम दोनों के मित्र डॉ. सुखरामदासजी बने। वे उरलीकांचन में डाक्टर थे। वहां सौ. आनंदीबाई नाईक उपचार के लिए गई थीं। साथ में उनकी पुत्री कु. वासंती नाईक भी इलाज की दृष्टि से वहां रही। तब ये लोग नरसिंहपुर (मध्यप्रदेश) रहते थे। श्री रामानंद दुबेजी डा. सुखरामदासजी के बचपन के मित्र होने से नाईक-परिवार

से और भी घनिष्ठता हो गई । डा. सुखरामदासजी ही कारण बने, नाईक-शर्मा परिवार का संबंध जोडने में । उन्होंने ही पू. विनोबाजी को लिखा और हम दोनों (मैं और वासंती) के बीच सक्रिय मध्यस्थता की । डा. सुखरामदासजी के साथ मेरा संबंध बनारस विश्वविद्यालय में आया, जब हम दोनों एक ही कमरे में ६ वर्ष सतत रहकर वैद्यकीय प्रशिक्षण लेते रहे । सगे भाई की तरह हम दोनों रहे। हमारे विवाह-संबंध का प्रस्ताव तो सबको मान्य हुआ । लेकिन बिहार में भूदान-आंदोलन में सबका आवाहन पू. बाबा ने किया था । उसमें हम दोनों को भी गया-रांची में काम करने की योजना बनी । बीच-बीच में बाबा के साथ पदयात्रा में भी शामिल होते रहे और उनके ही सुझाव पर १९५४ में बोधगया सर्वोदय संमेलन में हम दोनों विवाहबद्ध हुए । जहां बडी संख्या में लोग आये थे । दोनों परिवारों के सदस्य भी उपस्थित थे । इस बीच इस परिवार से संबंध आता रहा । अनेक लोगों की टिप्पणियां सुनने को मिलती रही । सबसे ज्यादा परिचय मनोहरजी दिवाण एवं हरिभाऊ मोहनी, जो अत्यंत उत्साह में एवं प्रसन्न थे, उनसे ही मिला । आर. के. पाटील के वे शब्द आज भी याद हैं कि "आप सौ. आनंदीबाई के संस्कारों में पली लडकी से शादी कर रहे हैं । दादाभाई तो निमित्त मात्र हैं ।" दादाभाई के बारे में पाटील साहब के ये उद्गार कई बार सुने । स्वयं पाटील साहब, दादाभाई, काशिनाथजी त्रिवेदी, काका वाळुंजकर के निकट सान्निध्य में आये और इन्हें अपना प्रेरणास्थान मानते रहे । "They are the soil of the earth" – ये लोग पृथ्वी के नमक हैं, यह पाटील साहब के उद्गार सुनकर बडी प्रेरणा और प्रसन्नता होती थी ।

पू. दादाभाई का त्याग, कष्ट सहने की क्षमता एवं स्वयंस्फूर्ति से, सहजता से अनेक जिम्मेदारियों का निभाना, फिर चाहे वह मध्य प्रदेश की पदयात्रा हो, डाकुओं के क्षेत्र में कार्य हो, इंदौर नगर का कार्य हो, विसर्जन आश्रम का संचालन हो, या इमर्जेंसी में जेल में २० महिने कारावास का जीवन बिताना हो । खादी के कार्य में उनका सारा जीवन ही बीता । उनकी रुचि बागबगीचे में भी रही । उस पर भी उन्होंने अपने अनुभव, चिंतन-मनन लिपिबद्ध किये हैं । काम करनेवालों की कमी नहीं । गांधी-विनोबा-जयप्रकाश के साथ जिन लोगों ने काम किया उनमें से पू. दादाभाई का स्थान प्रमुख माना जायेगा । जे. पी. के साथ दादाभाई का जो संबंध था उसका विवरण देने के लिए स्वतंत्र निबंध लिखना होगा । पू. विनोबाजी के साथ जैसा उनका निकट का संबंध था और

मुख्य आधार, भूदान आंदोलन के वे बने, वैसा ही लोकनायक जयप्रकाश नारायणजी के जन-आंदोलन में वे सहभागी बने। मध्य प्रदेश की पदयात्रा के एक विदाई-समारोह में जे. पी. के ये उद्गार कि – "दादाभाई उम्र में भी मुझसे बडे हैं, बडे भाई की तरह हैं। और जिस निष्ठा और सातत्य से वे भूदान-पदयात्रा करते रहे हैं, उसमें भी मैं कम ही पडूंगा। इसलिए उन्हें आशीर्वाद देने का मेरा अधिकार नहीं है। शुभेच्छाएं और शुभकामनाएं ही दे कसता हूं।" पर्याप्त रूप से इनके प्रति आदरसूचक है। पू. विनोबाजी के सान्निध्य और मार्गदर्शन में दादाभाई ने जो काम किये हैं, वे सर्वविदित हैं। इन कामों से वे इतने एकरूप बने कि स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं रखा। मध्यप्रदेश के गांवों से, शहरों से, व्यक्तियों से व्यापक और निकट का संपर्क और संबंध साधने में दादाभाई अद्वितीय रूप से यशस्वी हुए।

गांधीजी के सान्निध्य में उन्होंने राजनैतिक आजादी की लडाई लडी, उसमें कारावास की कहानी भी लंबी है। अपने जन्म-स्थान, हरदा से वे विधायक भी बने। लेकिन बाद में रचनात्मक कार्यों को समर्पित होने की दृष्टि से सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया। मूल में खादी-कार्य के निमित्त कई प्रसिद्ध परिवार एकसाथ रहे। फिर महाकोशल के खादी-कार्य की जबावदारी उठाई। हरदा से मूल, नरसिंहपुर, नागपुर और वहां से इंदौर की यात्रा का वर्णन काफी दिलचस्पीवाला है। प्रसंगवश उल्लेख मात्र करना ही यहां शक्य है। इतना ही नहीं, अपनी मौलिकता का भी परिचय पू. दादाभाई ने दिया है। जागीरदार के परिवार में जन्म लिया, लेकिन हमेशा फकीरी में जीवन बिताया। गरीबों की ही ज्यादा चिंता की। पारिवारिक जीवन और सार्वजनिक जीवन में सामंजस्य साधना कठिन काम होता है। बच्चों का संगोपन, शिक्षण आदि करना संस्थाओं में काम करनेवालों को कितना कठिन होता है, इसका ज्वलंत उदाहरण इनका परिवार रहा। ईश्वर की कृपा से सभी संतान योग्य एवं आदर्श, सेवापरायण एवं उच्च शिक्षा में निपुण बने और अपने-अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पू. दादाभाई स्वैच्छिक दारिद्रय का ज्वलंत उदाहरण हैं। श्रम-निष्ठा, सादगी, सरलता, अध्ययनशीलता, स्नेह की आर्द्रता धैर्य एवं कार्य की उत्कटता, समर्पित भाव, व्यवहार एवं अध्यात्म में समान एकरूपता आदि अनेक ऐसे गुण हैं जिनकी हम सबको अत्यंत आवश्यकता है। उनकी नम्रता, भव्यता, गरिमा, ऋषितुल्य ही हैं। संयमित जीवन योगी से कम नहीं। वह केवल शरीर का ही स्वास्थ्य

संभालने का कारण नहीं, अपितु मानसिक रूप से भी सदा प्रसन्न, संतुष्ट, निश्चल और संवेदनशील रहने में सहायक बना है। उनके परिवार पर संकट कम नहीं आये। कई लोगों की छोटी उम्र में ही असामायिक मृत्यु उन्हें देखनी पडी। संस्थागत चढाव-उतार आते रहे। कई तरह के अपमान सहने पडे। इमर्जेंसी में सगे-संबंधी, साथी भी दुराव करने लगे। आर्थिक अडचनें भी आती रहीं। लेकिन इन सबमें विचलित नहीं हुए। उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि उनका लाभ भी जब प्राप्त हुआ तो उसे छोड दिया। स्वातंत्र्य-सैनिकों को बहुत सुविधायें मिलती हैं। वे सब पू. दादाभाई ने जानबूझ कर स्वीकार नहीं की। उसी तरह सहज जब पुत्र और पुत्रवधु ने उन्हें अमरीका बुलाया, तो छह महिने रहकर आये और उसके भी विशेष आनंद में बहे नहीं। "सदा संतुष्ट जो योगी संयमी दृढ-निश्चयी। अर्पी मज मनो-बुद्धि भक्त तो आवडे मज।" पू. दादाभाई ने अनेक सद्‌वचनों का, गीता, उपनिषद तथा अन्य धर्मीय ग्रंथों से संकलन किया है। उनका उन्हें व्यक्तिश: लाभ हुआ ही होगा और दूसरों को भी हुआ होगा, लेकिन मुझे सहज बारहवें अध्याय का यह गीता का चौदहवां श्लोक उनका सारा जीवन दीखते हुए उपयुक्त लगता है। ऐसे ईश्वर-प्रिय भक्त के प्रति हम नतमस्तक हो, उनका अनुकरण करें, यही उनके प्रति हमारा सच्चा प्रेम और आदर होगा।

पू. दादाभाई का जीवन अनेक अनुभवों का भंडार है। उन्होंने अपने अनुभव लिपिबद्ध भी किये हैं। "श्री दादाभाई नाईक अभिनंदन समिति" उसे प्रकाशित करने की व्यवस्था करेगी तो एक बडी सेवा होगी। पू. दादाभाई का जीवन केवल एक व्यक्ति के दायरे में सीमित नहीं रहा। सर्वोदय के क्षेत्र में उनके प्रयोगों का लाभ व्यक्ति और संस्था, दोनों को प्राप्त करने योग्य हैं। इसीलिए समिति से यह विनंती है।

जीवेत् शरदः शतं-वर्धमानः – चलते-फिरते, सक्रिय रहकर।
पू. दादाभाई शतायु हों, यही ईश्वर-चरणों में प्रार्थना है।

मनोहर धाम, दत्तपुर
वर्धा (महाराष्ट्र)

– डॉ. रविशंकर शर्मा

८०वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में

मानव मुनि का अभिनंदन

हमारे साथी कृषि-गोसेवा संघ के उपाध्यक्ष श्री मानव मुनि का जन्म २६ अगस्त, १९१० को उज्जैन जिले के बेलडी ग्राम में श्री. सरदारमलजी जैन और श्रीमती सुंदराबाई जैसे संत-सेवक, दृढव्रति माता-पिता से हुआ। सेवा, परस्पर-प्रेम, सहयोग और प्राणियों के प्रति करुणा के संस्कार आपको परिवार से विरासत में मिले। आपका जन्मनाम दीपचंद है।

समाज की दयनीय हालत देखकर उनके मन में समाज-सेवा की भावना जगी और झाबुआ का आदिवासी इलाका और रतलाम जिला आपकी कर्म-भूमि बन गये।

सर्वोदय के पथिक

सन् १९३६ में महात्मा गांधी के इंदौर-आगमन पर आपको उनकी सेवा का सुअवसर सुलभ हुआ। स्वतंत्रता-आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए स्वदेशी, खादी व नशाबंदी इत्यादि रचनात्मक गतिविधियों में आपने योगदान किया। सन् १९५१ में आप आचार्य विनोबा भावे के संपर्क में आये और भूदान आंदोलन में सम्मिलित हो गये। सन् १९६० में मध्य प्रदेश में विनोबाजी की पदयात्रा के कार्यक्रम के आप संयोजक मनोनीत किये गये। १५ अगस्त १९६० में इंदौर में विसर्जन आश्रम की स्थापना हुई, जो आज तक आपकी रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र है।

राष्ट्रसंत विनोबाजी की पदयात्रा ४ सितंबर १९६४ को रींवा के पास चाकघाट ग्राम में थी। बाबा ने आपके सहज, निष्काम, गतिशील, निश्चल एवं निष्कलंक चरित्र से प्रभावित होकर "चरैवेति के केशर तिलक के साथ अपनी चादर ओढाते हुए दीपचंद के स्थान पर आपका "मानव मुनि" नामकरण कर दिया। इसी आशीर्वाद के संबल पर आप संपूर्ण देश में अपने रचनात्मक लक्ष्य की ओर निरंतर गतिशील बनें हुए हैं!

आप निष्काम समाजसेवी एवं मौन साधक हैं। मद्यनिषेध, अस्पृश्यता-निवारण, राष्ट्रीय एकता, गौरक्षा, गोपालन व पशुपालन एवं सर्वधर्म समभाव

की भावना से ओतप्रोत संत सेवक समुद्यम परिषद के संयोजक के रूप में आपने योगदान किया। देशव्यापी अनेक संस्थाएं, गीता भवन इंदौर, अणुव्रत आंदोलन, अ. भा. नशाबंदी परिषद, म. प्र. सर्वोदय मंडल, इंदौर खादी संघ, अ. भा. कृषि गौ-सेवा संघ, गुजरात गौरक्षा समिति, मध्यप्रदेश आचार्यकुल, श्री. मानव-मुनि गौरक्षा ट्रस्ट आदि के माध्यम से आपकी सेवाओं का यशोगान कर रही है। भगवान की कृपा से उनका स्वास्थ्य अच्छा है। इसी तरह स्वस्थ रहकर सौ साल तक समाज सेवा का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो यही हम सबकी ओर से मंगल कामना!

अ. भा. कृषि-गोसेवा संघ
गोपुरी, वर्धा (महाराष्ट्र)

राधाकृष्ण बजाज

गोरक्षार्थ सख्त कार्यवाही की जाएगी

कुकडेश्वर : अ. भा. कृषि गो-सेवा संघ के महामंत्री श्री केशरीचन्द मेहता और नीमच के गोरक्षकों का एक दल म. प्र. के मुख्यमंत्रीजी से मिला। यहां पधारे हुए जैन सन्तों के सानिध्य में चर्चा हुई। विद्यमान कानून का सख्ती से पालन, संशोधन एवं सीमावर्ती जिलों तथा मन्दसौर जिले में विशेष पुलिस दस्तों की मांग की। सप्ताह में एक दिन बूचडखाने बन्द रखने एवं नीमच सब्जी मण्डी मांस-मछली बाजार हटाने की भी मांग रखी गई। जैन संतों ने जीव दया हेतु कारगर उपाय करने हेतु विशेष ध्यान दिया।

मुख्यमंत्रीजी ने समस्या को बहुत गंभीरता से सुना और बताया कि सरकार की प्रबल इच्छा-शक्ति से ही गोवंश बच सकता हैं और सरकार की वह इच्छा-शक्ति जागृत हुई है। इस हेतु पुलिस और प्रशासन को विशेष निर्देश दिये जा रहे हैं। विद्यमान कानून का सख्ती से पालन करवाया जायेगा और कानून की कमियों को भी दूर किया जायेगा।

माननीय मुख्यमंत्रीजी ने गोरक्षकों के सद्प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने आव्हान किया कि विद्यमान गोशालाओं की दुर्व्यवस्था मिटाने हेतु कार्यकर्त्ताओं को आगे आना चाहिये। सरकार भी सहयोग करेगी।

पुरातन कृषि का एक अनोखा उदाहरण

अपने पूर्वजों के अनुभवों से सीखो, परंपरागत विधियों के महत्त्व को मत नकारो, यही मांग रही है उन लोगों की, जो आधुनिक कृषि तकनॉलाजी के दुष्प्रभावों के प्रति संवेदनशील तथा सतर्क हैं। इन दुष्प्रभावों की सूची लंबी है– रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग के कारण मिट्टी की उर्वरता में कमी आना, नहरों द्वारा लगातार सिंचाई से भूमि में बढत खारापन, संकर बीजों के व्यापक प्रयोग से फसलों के जीन कोष का संकीर्ण बनना, इत्यादि। अब पुरातत्वज्ञों ने कुछ ऐसी आश्चर्यजनक व अनोखी कृषि-विधियां खोज निकाली हैं, जो दक्षिण अमरीका के पेरु देश के पहाडी इलाकों में रहने वाले आदिवासियों ने ३००० साल पहले विकसित की थी। यह इलाका टिटिकाका झील के इर्दगिर्द, ऊंचाई पर फैला हुआ है। इन सरल, लेकिन प्रवीण विधियों के सहारे इन आदिवासियों ने अपनी फसलों को बाढ, सूखे और पाले पडने के खतरों से बचाकर रखा है। इन विधियों की खोज व पुर्नर्निर्माण लगभग १० साल से चल रहा है और इनका आधार वे प्राचीन चबूतरे हैं, जो संयुक्त राज्य अमरीका के विसकांसन विश्वविद्यालय के पुरातत्वज्ञों के एक समूह ने २० साल पहले खोज निकाले थे। पुरातत्वज्ञों ने देखा कि वहां के खेत ऐसे चबूतरों के विन्यास से बने थे जिनके बीचों बीच नहरें भी खोदी गयी थी।

वर्तमान पेरुवासी इन खेतों को वारु वारु कहते हैं। अनुमान है कि ये खेत एक ऐसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष है, जो इंका सभ्यता के पहले ही पेरु के पहाडी इलाकों में बसी थी। सोलहवीं शताब्दी में जब स्पेन के सैनिकों ने इंका सभ्यता का विनाश किया तो ये खेत भी प्रयोग में लाना बंद हो गये। इस उभरे खेत कृषि का पुर्नर्निर्माण प्रायोगिक पुरातत्व विज्ञान का एक प्रभावशाली उदाहरण है। प्रायोगिक पुरातत्व विज्ञान में पुरातत्वज्ञ न केवल खंडहरों को खोज निकालते हैं, बल्कि साथ में वे उन प्राचीन स्थितियों को पुनर्स्थापित करने की कोशिश भी करते हैं जिनमें उस सभ्यता के लोग रहते थे। पुर्नर्निर्माण का काम संयुक्त राज्य अमरीका के पेनसिलवेनिया विश्वविद्यालय के पुरातत्व / मानव-विज्ञान संग्रहालय के विशेषज्ञों ने १९८१ मे शुरू किया था। इन चबूतरों की खोज के पश्चात दक्षिण अमरीका के अन्य इलाकों में ऐसे सैकडों चबूतरे पाये गये हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ये चबूतरे उन दिनों कृषि-तकनालाजी का

आधार थे। टिटिकाका झील के इर्दगिर्द ही ऐसे चबूतरे २ लाख एकड क्षेत्र में फैले हुये हैं। आकार में वे १३ से ३३ फुट चौडे, ३३ से ३३० फुट लंबे और लगभग ३ फुट ऊंचे हैं। उनके बीच की नहरों का आकार व गदराई भी लगभग इतनी ही है। स्पष्ट है कि नहर की मिट्टी को जमाकर ही चबूतरे बने थे और इन पर फसलें उगाई जाती थी। रेडियोकार्बन कालनिर्धारण व अन्य तकनीकों की मदद से सबसे पुराने चबूतरों की आयु लगभग ३००० वर्ष आंकी गयी है। यानी वे ई. पू. १००० के आसपास बने थे। अगले २५०० सालों में इन चबूतरों को कई बार पुर्ननिर्मित भी किया गया था। इसीलिये चबूतरों पर मिट्टी की कई परतें पाई गई है।

चबूतरों व नहरों की मिट्टी के विश्लेषण से पता चला है कि वहां की मिट्टी की उर्वरक शक्ति आसपास के मैदानी इलाकों की मिट्टी से कई गुना अधिक थी। मिट्टी में पाये गये परागकणों के विश्लेषण से यह भी पता चला है कि लोगों ने आलू व क्विनोआ जैसी फसलें उगाई थी। मजे की बात तो यह है कि क्विनोआ एक ऐसी प्रोटीनयुक्त फसल है जो आज खाद्य फसल नहीं, बल्कि खरपतवार मानी जाती है।

पुरातत्वज्ञों ने लगभग २०० एकड भूमि पर चबूतरों व नहरों का पुर्ननिर्माण किया। इस प्रयोग में उन्होंने वही परंपरागत औजार भी अपनाए जो एंडीज पर्वतीय इलाकों में सदियों से प्रयोग में लाये जा रहे हैं। उदाहरण के लिये उन्होंने एक ऐसे हल का उपयोग किया जो पैरों से चलाया जाता है। प्रयोग के दौरान उन्होंने पाया कि शायद उन दिनों के लोग तीन-तीन के गुटों में हल चलाते थे। २ लोग मिट्टी को भूखण्डों में काटते थे और तीसरा व्यक्ति इन भूखण्डों को जमाकर चबूतरों का निर्माण करता था। किसी एक खेत में ऐसे लगभग १०–५० गुट एकसाथ काम करते थे, जो एक ही गांव या क्षेत्र के थे। पुरातत्वज्ञों ने वहां के आदिवासियों को भी ३० से १५० परिवारों के समूहों में इन प्रयोगों में शामिल किया। पुरातत्वज्ञों ने आलू की फसल उगाने की कोशिश की। गरमी के मौसम में उन्होंने नहरों के तल पर जमा हरी शैवाल की इकट्ठा करके चबूतरों पर फैलाया। यह शैवाल नाइट्रोजन का भरपूर स्रोत है। इनके उपयोग से खेतों को बारी-बारी परती छोडने की जरूरत नहीं पडती थी। उन्हें १० टन आलू प्रति हेक्टेयर का उत्पादन प्राप्त हुआ। इसकी तुलना में अधिक

रासायनिक खाद के प्रयोग के बावजूद आसपास के मैदानी इलाकों की पैदावार केवल १–४ टन प्रति हेक्टेयर थी।

प्रयोग के दौरान उन्होंने देखा कि नहर में जमा पानी के कारण १९८३ के सूखे का खेती पर अधिक प्रभाव नहीं पडा। ये उभरे चबूतरे १९८६ की बाढ में भी नष्ट नहीं हुये, जबकि मैदानी इलाकों के खेत बाढ के चपेट में डूबे थे। जमा पानी ने एक ओर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सौर ऊर्जा को सोखकर पानी ने चबूतरों की ऊपरी हवा को भी गरम रखा, जिससे फसल पर पाला नहीं पड पाया। खेतों का विन्यास जितना अधिक फैला होता है, सूक्ष्म जलवायु पर उतना अधिक प्रभाव पडता है। पुरातत्वज्ञों ने इस प्रयोग से यह सीखा कि ऐसे उभरे खेतों में कृषि न केवल सस्ती और श्रमसाध्य है, बल्कि वह पर्यावरण की रक्षा भी करती है। और पैदावार के हिसाब से यह खेती आधुनिक ऊर्जा तथा पूंजीयुक्त गहन कृषि-तकनॉलाजो से कई गुना बेहतर साबित हुई है। तो फिर यह खेती क्यों अचानक लुप्त हो गई ? पुरातत्वज्ञों का अंदाज है कि इंका सभ्यता स्थापित होने के साथ-साथ सत्ता तथा निवास के केन्द्र अन्य इलाकों में स्थानांतरिक हुए जिसके फलस्वरूप इन इलाकों का महत्व घटने लगा और ऐसी खेती भी धीरे-धीरे खत्म होने लगी। पर पुरातत्वज्ञों का कहना है कि इन विधियों की पुनर्स्थापना तीसरी दुनिया के देशों के लिये फायदेमंद होगी। खासकर उन न्यूनतम उर्वरता वाले इलाकों में जहां संसाधनों की सख्त कमी है और जहां आधुनिक कृषि तकनॉलाजो आज तक नहीं पहुंची है।

('इतवारी अमृत संदेश', रायपुर से)

☆ ☆

कतल से ७२ बछडे बचाये
पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य

२५ जून की शाम को यशोवर्धन नगर, मंदसौर पुलिस थाना के प्रभारी श्री. डी. पी. वर्मा और उनके साथी पुलिसवालों ने ट्रक नंबर MKV 5386 को चारों ओर से ताडपत्री का ढक्कन खोलकर देखा तो उसमें ७२ बछडे ठूंस-ठूंस कर भरे हुए पाये, उन पर केस दायर की गई। कोर्ट द्वारा सचिव कृषि-गोसेवा संघ नीमच को वे सुपूर्त किये गये। ट्रक-मालिक और पशुमालक मुलतानपुरा मुश्ताक हैं।

नर्मदा परियोजना : लोग क्या कहते हैं ?

रमेश बिल्लौरे : विजया पाराशर

[नर्मदा वांधों के पक्ष और विपक्ष में वहुत कुछ कहा और लिखा गया है। एक ओर सरकारी पक्ष इन वांधों से होने वाले फायदों को वढाचढाकर दिखा रहे हैं, तो दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि यह परियोजना राष्ट्रहित में नहीं है, क्योंकि इनसे जंगल व खेती की जमीन डूवने से होने वाली पर्यावरण की क्षति और उजडने वाले लोगों के कष्ट को ध्यान में रखा जाय, तो लाभ से हानि कहीं अधिक होगी।

लेखकद्वय ने पिछले दिनों नर्मदा-सागर डूब-क्षेत्र के लोग क्या चाहते हैं, यह जानने के लिए खंडवा जिले के लगभग ४० गांवों में घूमकर लोगों से वातें की। उससे जो लोगों के विचार मालूम हुए वह संक्षेप में यथासंभव उन्हींके शव्दों में प्रस्तुत है। – संपादक]

जहां तक नर्मदा सागर का सवाल है, इस बांध से उतनी सिंचाई भी नहीं होगी जितना क्षेत्र डुवोया जा रहा है। कारण ३० प्रतिशत जमीन छिछली है और करीब ४० प्रतिशत दलदल से वेकार हो जाएगी। इसी तरह वास्तविक बिजली (फर्म पावर) २२० मेगावाट है, जो बाद में १०० मेगावाट रह जाएगी। इस बिजली का भी अधिक हिस्सा उदवहन नहर व ३५ प्रतिशत भूगर्भ जल से सिंचाई करने में चला जाएगा तो यह थोडी-सी विजली और सिंचाई किस कीमत पर मिलेगी ? इस वांध से तो ९०,००० हेक्टर क्षेत्र डूबेगा उसमें ४५,००० हेक्टर कृषि-भूमि व ४०,००० हेक्टर जंगल शामिल है व २२५ गांवों के करीब २ लाख लोग प्रभावित होंगे। इसके साथ सरदार सरोवर भी जोडें तो ५०० गांवों के तीन लाख से अधिक लोग इन बांधों से उजाडे जाएंगे।

मगर फिर भी सरकार यह प्रचार कर रही है कि यह बांध राज्यों के लिए वरदान है और कुछ "वाहर" के लोग गडवड कर रहे हैं, जवकि जिन्हें डूबना है वे तो चुप हैं जिसका अर्थ है कि उन्होंने बांध को स्वीकार कर लिया है।

सवाल यह है कि लोगों से पूछा कब गया था कि उन्हें बांध चाहिए या नहीं ? कहने के लिए यह लोगों की सरकार है, मगर लोगों से बिना पूछे, लोगों की मर्जी के खिलाफ और लोगों के हितों के खिलाफ अधिकतर काम हो रहे हैं। और यह इसलिए चल रहा है क्योंकि लोग चुप रहते हैं और उनकी चुप्पी को स्वीकृति मान लिया जाता है। लोगों की कोई इज्जत नहीं है। उन्हें भेड़-बकरियों जैसा समझा जाता है और जब चाहे अपने घर-खेत से हटा दिया जाता है। सवाल यह है कि जिनके घर-जमीन डुबोयी जाती है वे क्या राष्ट्र के नागरिक नहीं हैं ? क्या उनका हित देश का हित नहीं है ? क्या राष्ट्र की परिभाषा में चंद बड़े लोग ही आते हैं जिनके फायदे को विकास की संज्ञा दी जाती है ? यह कहा जाता है कि कुछ लोगों को तो तकलीफ उठानी ही पड़ेगी जिससे दूसरे आराम से रह सकें। पहली बात तो यह तय करने का हक उन्हें किसने दिया कि कौन त्याग करें व कौन उसका लाभ उठाएं ? और जब यह परियोजना ही राष्ट्रहित में नहीं तो लोग क्यों त्याग करें ? और फिर हमेशा गांव के गरीब, आदिवासियों से ही त्याग करने को क्यों कहा जाता है, ताकि शहर के कुछ बड़े लोगों को उसका फल मिलें ? क्या हमारे संविधान में हरएक व्यक्ति को जीने का व अपनी रोजी-रोटी कमाने का हक नहीं दिया है ?

नर्मदा बांधों की योजना बनाते समय और बाद में भी न तो लोगों को इनसे होने वाले लाभ-हानि की सही जानकारी दी गई और न उनकी राय ही ली गई कि यह बांध बनाया जाए या नहीं या वे लोग हटने को तैयार हैं या नहीं ? इसलिए लोग क्या चाहते हैं, यह जानने के लिए हमने पिछले दिनों नर्मदा सागर डूब क्षेत्र में खंडवा जिले के लगभग ४० गांवों में घूमकर लोगों से बातें की। उससे जो लोगों के विचार मालूम हुए वह संक्षेप में व जहां तक संभव उन्हींके शब्दों में यहां प्रस्तुत हैं।

हरसूद की बसोड परिवार की शकुन बाई का कहना था कि "यह बांध नहीं बनना चाहिए। हमें यहां से हटना पड़ा तो कहां जाएंगे ? कैसे बसेंगे ? बच्चों का क्या होगा ? मजदूरी कहां मिलेगी ? यह हरसूद मौके की जगह है। यहां तो सब जमा हुआ है। नई जगह गए तो बांस कहां मिलेंगे, टोकरियां बनाने के लिए ? टोकरियां बिक्री कहां करेंगे ? बाहर जाकर भूखों मरेंगे। धंधा नहीं हुआ तो बच्चों को कहां से खिलाएंगे ? उजड़ने की तकलीफ दूसरा नहीं

समझ सकता । बांध वालों का अपना घर बर्बाद हो तो पता चलेगा । हम डूबेंगे पर, हटेंगे नहीं ।"

हरसूद के ही एक छोटे दुकानदार मोहम्मद शमी का कहना था – "अगर बांध बनता है तो सिवाय हमारी बर्बादी के कोई रास्ता नहीं है । क्योंकि मुआवजे की तो कोई उम्मीद नहीं, वह कयामत तक भी नहीं मिलेगा । हम लोग खानाबदोश से बदतर जिंदगियां गुजारेंगे और दर-दर की ठोकरें खाते फिरेंगे । हमारी और हमारे परिवार की जिंदगी जिंदा लाश की मानिंद हो जाएगी । हमें पक्का विश्वास है कि गवर्नमेंट एक इंच जमीन नहीं दे सकती । क्योंकि जब छोटे बांध वालों को अभी तक न तो कहीं बसाया गया है, न उन्हें मुआवजा दिया गया है और न ही खेती की जमीन दी गई । जब उन्हें उनका हक नहीं मिला तो बडे बांध से उजडने वालों को क्या मिलेगा ? सरकार हमारे लिए है, हम सरकार के लिए नहीं । आज तक तो हमारे प्रतिनिधि हैं, सांसद व विधायक जिन्हें हमने हमारी आवाज पहुंचाने के लिए सरकार के द्वार तक भेजा, उन्होंने आज तक हमारे बीच आकर बांध के मुतल्लक हमसे कोई चर्चा नहीं की और न ही हमें कोई तसल्ली-बख्श उनसे कोई जवाब मिला । जाहिर है कि हमारी जिंदगियों पर बहुत बडा खतरा मंडरा रहा है । इन सब बातों को सोचकर हमने यह निर्णय लिया है कि हम कदापि-कदापि यहां से नहीं हटेंगे । दर-दर की ठोकरें खाने से वहीं डूब कर मर जाना बेहतर है । हमारी जिंदगियों से सरकार को खिलवाड करने का कोई अधिकार नहीं है । सरकार को चाहिए कि हमारी बातों को ध्यान में रखकर अपने बरबादी वाले बांध के निर्णय को बदलें (और वह निर्णय लें) जो हमारे हक में हो । खुशहाली की जिंदगी बसर करने का जो हमारा हक है हमें वापस कर दें ।"

सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि "इस बांध को जनता ही रोक सकती है । जनता अगर यह महसूस कर लें कि उसकी इतनी बडी ताकत है कि एक बांध तो क्या, दुनिया के हर विनाशकारी योजना को रोक सकती है । हमें वक्त आने पर पुनासा डेम (नर्मदा सागर) पर काम रोको आंदोलन छेडना पडेगा ।"

अभावां गांव की वृद्धा रामप्यारी के मत से "गांव के लोगों में समभाव होना चाहिए । पहल गांव में व फिर डूब के २५४ गांवों में एका होना चाहिए और आदमी बाई (महिलाएं) सब मिलकर बांध रोकने जाए तो बांध रुक सकता है ।"

जूनापानी गांव की खेत-मजदूर मेहताब का कहना था : "एक व्यक्ति के जाने से चिन्ता होती है तो पूरा गांव बिछुडने से कितना दुःख होगा ? फिर हमें तो भीख मांगना भी नहीं आता। बाहर जाकर हम भूखों मरेंगे।"

नांगपुर गांव के कृपक मानसिंह का कहना था कि डूब क्षेत्र के गांवों के लोगों को आपसी झगडे भुलाकर एक होकर लडना पडेगा। शोभाबाई का भी यही कहना था। इसी गांव के छगनलाल ने कहा कि बांध के अफसरों के साथ पूरा असहयोग करना चाहिए। गांव में उनसे कोई बात न करें।

गन्नोर गांव की खेत-मजूरन सेतुन आपा और अमीना बी का मत था– "हम हमारे गांव में हैं तो आधी रोटी खाकर भी खुश हैं। रहने को झोपडी है। मजदूरी भी मिल जाती है। बाहर निकले, तो क्या होगा ? यहां तो मही (छाछ) भी मुफ्त मिल जाता है। पैसा न हो तो भी काम चल जाता है। शहर में पैसा न हो तो भगा देते हैं। शौचालय की सुविधा के लिए भी पैसे लगते हैं। सरकारी अफसर कुछ भी कहें, हमें न तो जमीन मिलने वाली है और न मुआवजा। हम गांव नहीं छोडेंगे और इसी जमीन पर अंतिम सांस लेना चाहते हैं। किसी सरकार को हमें बेघर करने का हक नहीं है।" जलवां की राजूबाई के अनुसार –"खेत जमीन नहीं मिलेगी और मजूरी भी नहीं मिलेगी। अगर हम सब बांध रोकने की कोशिश करें तो बांध रुकेगा।"

मगर अब धीरे-धीरे वातावरण बदल रहा है। लोगों को लग रहा है कि वे एक हो गये तो बांध को रोक सकेंगे।

गुजरात में सरदार सरोवर डूब क्षेत्र में लोगों को चार साल से अधिक पुनर्वास व मुआवजे की लडाई के बाद अनुभव हुआ कि सरकार झूठ बोल रही है व अपने वायदे पूरे नहीं कर सकेगी। क्योंकि न तो विस्थापितों के लिए जमीन है और न उचित मुआवजा ही मिल सकेगा। जिन सात गांवों को हटाया गया उनका अनुभव दुखद है। या तो विस्थापितों को जमीन नहीं मिली है, और मिली है तो बेकार है जिसमें कुछ पैदा नहीं हो सकता। कहीं विवादास्पद जमीन (जिसमें दूसरे गांव के चरागाह शामिल हैं) दे दी है, जिससे आपस में झगडे हुए या डूब में आने वाली जमीन ही दे दी है, जहां से थोडे समय बाद फिर हटना पडेगा। एक ही गांव की जमीन का वही टुकडा अलग-अलग गांव वालों को दिखाकर धोखा दिया गया। नयी जगह बसे लोगों में मृत्यु- दर (विशेषकर बच्चों की) बढ गयी है।

सरदार सरोवर बांध के लिये बनायी अफसरों की कालोनी के लिए जिन लोगों की जमीन ली गयी उन्हें अब तक नहीं बसाया गया। जहां विस्थापितों में आदमी, मजदूरी तलाश कर रहे हैं, वहां औरतें कालोनी के अफसरों के घरों में बर्तन मांजने, कपडे धोने का काम कर रही हैं।

इसलिए अगस्त १९८८ से सरदार सरोवर बांध से प्रभावित होने वाले तीनों राज्यों के विस्थापितों ने पुनर्वास की मांग छोड इस बांध का ही विरोध करने का निश्चय किया। उन्हें यह भी समझ में आ गया कि न केवल सरदार सरोवर व नर्मदा सागर बांधों के डूब क्षेत्र के लोगों की लडाई को जोडना जरूरी है, बल्कि देश के अन्य भागों में इसी तरह विनाशकारी परियोजनाओं के विरुद्ध चल रहे संघर्ष से जुडे लोगों को भी एक होकर इस जनविरोधी कार्यों के खिलाफ लडना होगा। तभी सफलता मिल सकेगी। हरसूद में गत वर्ष २८ सितम्बर को सारे देश के ५०,००० से अधिक लोगों का एकत्र होना इस एकता का प्रतीक था और इस संगठित सफल जनसंघर्ष की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है। (सप्रेस द्वारा पेनोस, पर्यावरण कक्ष एवं गांधी शांति केंद्र के सहयोग से) ★ ★

गोवंश-हत्या रोकने में

योगिराज देवरहा बाबा सेवा समिति लार रोड, देवरिया क्षेत्र का सराहनीय कार्य

★ नौलार पुलिस चौकी के प्रभारी श्री. नजरूल हसन ने गत दिनों अपने गश्त के दौरान वध हेतु १२ गायों और बछडों को बरामद किया और अपराधियों को बंदी बनाया।

★ मगहर कोतवाली पुलिस ने अवैध ढंग से वध हेतु दो ट्रकों मे ले जा रहे २६ पशुओं को छुडाया और पशु-क्रूरता के तहत चालान कर दिया। क्षेत्राधिकारी मगहर और एस. आय. श्री पी. एन. पाण्डेय ने सक्रियता बरती।

★ थाना हाटाअन्तर्गत पिपरही भडकुलवा के पास तीन ट्रकों पर जा रहे ४१ वूढे बैलों को हाटा पुलिस ने ड्रायवर सहित क्रूरता के अधिनियम के तहत ५ बेपारियों को गिरफ्तार किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिहार होकर बंगाल में ये जानवर लेजा रहे थे।

पर्यावरण और समाज

पर्यावरण के मुद्दे को लेकर आज जितनी चौकन्नी दृष्टि, चेतना तथा चिंता पूरे विश्व-स्तर पर व्याप्त है, उतनी लगभग दो दशक पूर्व तक नहीं थी। वस्तुत: सामाजिक अंतर्विद्या प्रकृति के साथ इतनी व्यापक हो गई है कि इससे संपूर्ण मानव जाति को प्रभावित करने वाली स्थिति उत्पन्न होती है और यहीं पर्यावरणीय प्रश्न का प्रारंभ है।

पर्यावरण तथा मनुष्य अभिन्न है। इन्हें एक-दूसरे का सहभागी माना जाता है। पर्यावरण के भौतिक तथा मानवकृत दो भेद हैं। प्रकृति आदिभौतिक तथा वनस्पति आदि मानवकृत है। प्रकृति का प्रत्येक भाग चाहे वह उत्ताल सागरीय तरंगे हैं या उत्तुंग शैल श्रृंग, अरण्य है या भूमि, वायु है या वन्य प्राणी, सभी सीधे-सीधे पर्यावरण से जुडे हैं। प्रख्यात चिंतक तथा विचारक कार्लमार्क्स का विचार है कि मनुष्य प्रकृति की ही एक शक्ति के रूप में प्रकृति के मुकाबले खडा होता है। इस तरह वाह्य विश्व को प्रभावित करके मनुष्य स्वयं भी अपनी प्रकृति परिवर्तित कर लेता है। (मार्क्स : पूंजी, वाल्यूम १, पृष्ठ २०२-२०३)

विज्ञान की उत्तरोत्तर प्रगति ने मानव को प्राकृतिक विश्व पर अतिक्रमण के लिए उत्प्रेरित किया और मनुष्य ने परिणाम की चिंता किये बगैर जैवमण्डल पर तीव्र आक्रमण किये। फलस्वरूप निकट भविष्य में इसके अनेक दुष्परिणाम की आशंका बलवती होती जा रही है। अपने को विकासशील, उन्नत तथा सभ्य कहलाने की ललक में मानव समुदाय स्वयं अपना नुकसान कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि सभ्यता जब स्वत: स्फूर्त ढंग से प्रगति करती है तो वह अपने पीछे केवल रेगिस्तान छोडती जाती है। (मार्क्स-एंजेलस : सेलेक्टेड कॉरेस्पान्डेस – पृष्ठ १९० पर मार्क्स का पत्र २५३/१८६८)।

विकास की मजबूरी तथा आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण कई विकासशील राष्ट्र पर्यावरण सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए अपनी प्राकृतिक संसाधनों की सीमा से अधिक दोहन कर बैठते हैं। इसमें दो मत नहीं है कि प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिससे संपूर्ण मानव समाज तथा भविष्य के लिए तात्कालिक संकट उत्पन्न

हो रहा है। (संयुक्त राष्ट्र संघ का 'निरस्त्रीकरण एवं विकास' पर १९८१ की रपट)

वैसे तो पर्यावरण में स्वसंरक्षण की प्रवृत्ति पायी जाती है, तथापि वायुमण्डल, मिट्टियाँ, निर्बाध प्रवाहमान जल अपनी वर्तमान अवस्था में ऐसे अस्थिर घटक हैं, जो स्वसंरक्षण नहीं करते, अतः इनकी सुरक्षा आवश्यक है। फ्रेडरिक एंजेल्स ने मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहा था कि मनुष्य को अपने द्वारा प्रकृति पर किये गये विजय से गर्वोन्मत्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति अपने ऊपर किये जाने वाले सभी विजय का बदला अवश्य लेती है... हम प्रकृति पर किसी विजेता की भाँति शासन नहीं करते, अपितु उस पर निर्भर रहते हैं। (डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर, पृष्ठ १८०-१८२) पर्यावरण पर कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था 'अर्थस्केन' ने 'पर्यावरण और संघर्ष' शीर्षक से प्रस्तुत अपनी रपट में कुछ चौकाने वाले तथ्य उजागर किये हैं जिसमें कहा गया है कि पर्यावरण प्रदूपित होने से संघर्ष बढते हैं, भूक्षरण, कृषि, उपज में ह्रास, बाढ की विभीषिका, अनावृष्टि तथा अकाल होते हैं।

एक समय था जब पर्यावरण का प्रश्न मुख्य रूप से धनिकों से सम्बद्ध था, किन्तु अब विभिन्न आंदोलनों, जिनमें चिपको आंदोलन प्रमुख है, में जन-साधारण को जागरूक बना दिया है। जब पर्यावरण को हानि पहुंचती है तो इसका दुष्प्रभाव प्रायः गरीबों पर ही पडता है।

पर्यावरण संरक्षण मात्र राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, न ही इसे क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है। विषाक्त धुंए, जीवन को प्रभावित करने वाले औद्योगिक प्रदूषण से पर्यावरण को खतरा उत्पन्न होता है। वातावरण में कार्बन डाइ-आक्साइड के जमाव से ओजोन परत के खतरे बढ रहे हैं। इसीको लेकर अभी हाल ही में लंदन में एक सम्मेलन हुआ। मार्च १९८९ में स्विट्जरलैंड के बाजेल नगर में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ओर से विषैले औद्योगिक अपशिष्ट को अविकसित देशों में फेंकने से रोकने के प्रश्न पर भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए, जिसमें १०५ राष्ट्र भयानक खतरों वाले औद्योगिक अपशिष्ट के निर्यात को नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संधि पर सिद्धांत रूप से सहमत हुए। यद्यपि यह एक उपलब्धि है, तथापि विषैले औद्योगिक अपशिष्ट उत्पादकों में अग्रणी अमेरिका द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर न करना वस्तुतः चिंतनीय है।

वस्तुत: विश्व वायुमंडल सर्वाधिक प्रदूषित है। मनुष्य पर्यावरण में घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्टों का व्यापक मात्रा में विसर्जन करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानव समाज औद्योगिक इकाइयों में जिन रसायनों को प्रयुक्त करता है, उनमें से ४००० उसके लिए हानिकारक है। पूरे विश्व में प्रतिवर्ष २५००० से भी अधिक नवीन रसायनिक यौगिकों का संश्लेषण होता है, जिनमें से लगभग ३०० उत्पादन में प्रयुक्त होकर पर्यावरण प्रदूषित करते हैं। वायुमंडल में औद्योगिक अपशिष्ट विसर्जन के साथ-साथ मलयुक्त औद्योगिक वहिप्रंवाह से आज की अधिसंख्य नदियों – टेम्स, डेन्यूब, हडसन, लेक सुपीरियर, गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, गोमती, गोदावरी, हुगली, दामोदर, पेरियार आदि अनेक– के जल प्रदूषित हो चुके हैं। व्यापक स्तर पर जलीय जीवों के आखेट होने से जल के अपशिष्ट से जल प्रदूषण बढ रहा है, क्योंकि जलीय जीव इनका भक्षण करते थे।

वन-संपदा, वन्य जीव-जंतु, अरण्य पर हम निरंतर प्रहार कर रहे है, जिससे न केवल पर्यावरण-संरक्षण की ही समस्या उठ खडी हो चुकी है, वरन् समाज का अस्तित्व भी खतरे में पड गया है।

('नवभारत' दैनिक नागपुर से)

– गोपालजी गुप्त

※ ※

द. डरबन (दक्षिण आफ्रिका) में गांधीजी का सन्मान

दक्षिण आफ्रिका के नाताल सूबे की राजधानी पीटरमैरित्सबर्ग की सिटी कौंसिल ने गांधीजी की याद में उनकी मूर्ति खडी करने तथा रकाबियां लगाने की योजना को स्वीकृति दी है। यहीं के स्टेशन पर गांधीजी को रंगभेद का पहला अनुभव हुआ था, जबकि उनको पहले डिब्बे से एक गोरे की आपत्ति पर उनको धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया था।

हम भी पुनर्वास चाहते हैं –
लेकिन मानवीय मूल्यों का

सुन्दरलाल बहुगुणा

"जब तक अंतिम विस्थापित का पुनर्वास न हो जाए, तब तक काफर बांध नहीं बनने देंगे" – इस मांग को लेकर टिहरी में कुछ लोगों द्वारा धरना प्रारंभ किए जाने के बाद टिहरी बांध पुनः चर्चा का विषय बन गया है। हम भी पुनर्वास चाहते हैं, लेकिन केवल उन्हीं लोगों का नहीं, जिन्हें चंद वैभवशाली लोगों के लोभ-लालच की तुष्टि के लिए अपने पैतृक घरों से जबर्दस्ती उखाडा जा रहा है। हम इस हृदयहीन कार्यवाही का जडमूल से विरोध करते हैं। किसी भी व्यक्ति को उस स्थान को छोडने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, जिसके साथ वह सदियों से भावात्मक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से एकात्म होकर रहा हो। पेडों की तरह लोगों की जडें भी मिट्टी में होती हैं और एक बार उससे उखड जाने पर कभी भी उनकी खुशी; स्वास्थ्य और संतोष वापस नहीं लौट सकता।

मानव इतिहास में विस्थापन सबसे बडी त्रासदी रही है। दुर्भाग्य से तथाकथित विकास – बडे बांध, खनन और औद्योगिक परियोजनाओं – के नाम पर प्रतिवर्ष लाखों लोगों को विस्थापित किया जाता है। ये मुख्यतः दूरदराज के पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों के निवासी होते हैं। इन सीधे और सरल लोगों ने सादगी और प्रकृति के साथ मैत्री का जीवन बिताकर जंगल, जल और जमीन के प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखा था, लेकिन अब हमारे विकास नियोजनकर्त्ताओं की गिद्ध दृष्टि इन पर पडी है। इन संसाधनों का नगरों और अधिक विकसित क्षेत्रों में निर्यात किया जा रहा है। इसका औचित्य सिद्ध करने के लिए वे कहते हैं कि वे उत्पादन बढाना चाहते हैं, अधिक लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन यह अधिक उत्पादन और अधिक रोजगार उन क्षेत्रों में जहां पर संसाधन हैं क्यों नहीं पैदा किया जाता? यह हास्यास्पद है कि भागीरथी का पानी टिहरी से ३०० कि. मी. दूर दिल्ली में पीने के और पहले से ही सबसे अधिक सिंचित पश्चिमी उ. प्र. में सिंचाई के लिए ले जाया

जाएगा। बिजली भी उत्तरी ग्रिड में पहुंचाई जाएगी, लेकिन टिहरी बांध जलाशय के चारों ओर रैका, धारमण्डल, जुवा, जुवा उदेपुर, दिचली-गमरी, मन्यार, साठजुवा और रवास पट्टी के प्यासे गांवों को, जो नदी को देख सकते हैं, इस नदी का पानी नहीं मिल सकगा, हटवाल गांव और सिराई के बंजर मैदानों को जो नदी से ३० मीटर से भी कम ऊंचाई पर हैं, सिचाई के लिए पानी नहीं मिल सकता।

हमारे पास हिमालय के पुनर्वास की, यहां के लोगों को मिट्टी और पानी से सम्पन्न बनाने की और सारे देश के लिए हिमालय स्थायी समृद्धि का स्रोत बनाने की योजना है इस पहाड के खिसकते हुए ढलानों को सघन वृक्षों से ढंककर। लेकिन यह मौजूदा नीति में, जो हिमालय को इसके वन, मिट्टी और पानी की बिक्री करके तथा यहां के लोगों को उखाडकर चंद पूंजीपतियों के लिए पांचतारा होटलों का स्थान सुरक्षित कर पैसा कमाने का साधम मात्र मानती हैं, बुनियादी परिवर्तन करने से ही संभव हो सकती है।

टिहरी बांध भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया है, क्योंकि बांध बनाने वालों ने कई भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया है, क्योंकि बांध बनाने वालों ने कई भ्रष्ट तौरतरीकों को जन्म दिया है। उन्होंने केवल निर्माण सामग्री की बिक्री और किसी न किसी बहाने पैसा खींचने का सिलसिला जारी रखा है, बल्कि कई ऐसे तौरतरीके भी निकाले हैं, जिससे वे सभी लोग जिनके पास आम जनता अपनी फरियाद लेकर न्याय पाने की आशा रखती हैं, वे बांध बनाने वालों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। कुछ प्रचार माध्यम, जिनमें सरकारी माध्यम भी शामिल हैं, टिहरी जल विकास निगम के झूठे प्रचार को फैलाने के भोंपू बन गए हैं। इससे उनकी प्रामाणिकता समाप्त हो गई है। वे सत्य को दबा रहे हैं। सरकार का स्वयं का यह दावा कि वह नागरिकों को सब सूचनाएं उपलब्ध कराएगी, झूठा साबित हो गया है। उसने इस बांध के संबंध में भूंबला समिति और ढौंढियाल समिति की रिपोर्टों तथा नवादा विश्वविद्यालय की भूकम्प प्रयोगशाला के निर्देशक प्रो. ब्रुने की टिप्पणी सहित डा. विनोद गौड के पत्र को गोपनीय कर दिया।

हर बार यह प्रचारित किया जाता है कि रुसी विशेषज्ञों ने बांध का प्रकल्प सही बताया है। ये विशेषज्ञ कौन हैं ? क्या ये भी बांध परियोजना के

उन सलाहकारों जैसे हैं, जिन्हें इस परियोजना से परवरिश मिलती रही है या वे स्वतंत्र वैज्ञानिक हैं ? उन्हें स्वतंत्र वैज्ञानिकों के आमने-सामने क्यों नहीं बिठाया जाता ? टिहरी में कार्यरत रुसी विशेषज्ञों का बयान दर्ज कर तो भूंवला-समिति इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है कि "अपने वर्तमान रूप में इस परियोजना को स्वीकृति देना एक बहुत ही गैरजिम्मेदाराना काम है ।"

टिहरी बांध के भूकम्पीय और दूसरे पर्यावरणीय खतरों संबंधी गंभीर आपत्तियों के बावजूद भी इस बांध के निर्माण को जारी रखना, बांध-जलाशय के चारों ओर नीचे गंगा के मैदान में रहने वाले लाखों लोगों को जलप्लावित करने का का जान-बूझकर किया जाने वाला प्रयास माना जाएगा। इस दैत्याकार बांध के टूटने के तत्कालिक शिकार देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून और रुडकी होंगे । यह आश्चर्य की बात है कि जो राजनेता बढ-चढकर इस विनाशकारी बांध की वकालत करते रहे हैं, अब शायद वे रतौंधी के साथ-साथ दिनौंधी से भी पीडित हो गए हैं, जिससे वैज्ञानिकों द्वारा उजागर किए गए इसके खतरों के बाद, चुप्पी साधे हुए हैं ।

अब यह केवल विकास और विनाश का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि "जिंदा रहने के" मूलभूत नागरिक अधिकार का हनन है । टिहरी वेदांती संत स्वामी रामतीर्थ की तप:स्थली और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए टिहरी जेल में ८४ दिनों का अनशन करने वाले मानव अधिकारों के महान रक्षक श्री देव "सुमन" की बलिदान-स्थली रही है । कोई भी स्वतंत्रताप्रेमी इस प्रेरणा-भूमि में जिंदा रहने के अधिकार की हत्या बर्दाश्त नहीं कर सकता ।

* *

आज यहां से अंग्रेजों और मुसलमानों को मारकर या हटाकर गाय को बचाने से मुझे क्या सन्तोष होगा ? मुझे तो तभी सन्तोष होगा, जब सारी दुनिया में सभी गाय को बचानेवाले बन जायं, और यह काम शुद्ध अहिंसा के पालन से हो सकता है ।

अब गोरक्षा का मेरा अर्थ समझ में आया होगा । गोरक्षा का स्थूल अर्थ अपनी स्थूल गाय की रक्षा करना है । सूक्ष्म आध्यात्मिक अर्थ यह है कि प्राणिमात्र की रक्षा की जाय ।

– गांधीजी

हम विकास की ओर या विनाश की ओर ?

प्रामाणिकता बढी या भ्रष्टाचार ? भूजल घटा या बढा ?

गरीब की गरीबी बढी या घटी, चंद व्यक्ति धनवान हुए या अधिकांश, नैतिकता बढी या घटी, चारित्र्यवाले बढे या घटे, शारीरिक तंदुरुस्ती बढी या घटी, डाक्टर बढे या घटे, हॉस्पीटल बढे या घटे ? सेना में पहले ४२-४४ इंच की छातीवालों को भरती करते थे, आज ३६ इंचवाले मिलने कठिन हो गये ? इसका क्या कारण है ? अन्न शुद्ध मिलता है या जहरीला, स्वादिष्ट मिलता है या निकृष्ट, फूलों में सुगंध बढी या घटी, शांति बढी या घटी, हिंसा बढी या अहिंसा, पशु-हत्या बढी या घटी, चमडे का निर्यात बढा या घटा, मांस का निर्यात बढा या घटा ? शुद्ध दूध, दही, घी, मक्खन, आसानी से मिलते हैं या कठिनता से ? उत्पादकता बढी तो चीजें सस्ती हुई या महंगी, शिक्षण-पद्धति का तरीका अच्छा है या बुरा ? दारू पीनेवाले, मांस खानेवाले बढे या घटे, स्त्रियों पर अत्याचार बढे या घटे, न्यायालयों से न्याय सुलभता से मिलता है या कठिनता से, वृक्षों की कटाई से जंगल आबाद हुए या बरबाद ?

सुबह का भटका शामको घर आया, तो भविष्य सुधर सकता है

"भारत पश्चिम की ओर दौड रहा है और पश्चिमवाले भारत की ओर"

भारतीय संस्कृति व परंपरा के अनुसार

जुआ, डकैती, स्मगलिंग, वेश्या-व्यवसाय, पशु-कतल मांस, मदिरा, चमडों के व्यवसाय को व्यापार की संज्ञा नहीं दी जा सकती। जिस प्रकार मनुष्य को मारकर उसके अंग-प्रत्यंग बेचकर पैसा कमाना कभी व्यापार नहीं माना जा सकता और कोई ऐसा व्यापार करता था, तो अधमाधम माना जाता था।

संसार में मौजुदा पशु-संख्या : भारत का नंबर सबसे नीचे

भारत का पशुधन तेजी से नष्ट

पशुजाति	१९५१	१९६१	१९७१	१९८१	१९९१	२००१	२०११
गाय-बैल (कैटल)	४३०	४००	३२६	२७८	२०२	११०	२०
भैंस-भैंसे	१२०	११७	१०६	१००	९०	६०	२०
बकरे	१४१	१३९	१२९	११८	१०६	उत्तर नहीं	उ. न.
भेडे	१०८	९२	७४	६२	५०	,,	,,

अब आपको उत्सुकता होगी कि हम कुछ बाहरी देशों में प्रति हजार व्यक्तियों के पीछे कितने पशु हैं इसे भी देखें, ताकि हमें सही ज्ञान होगा कि हम हमारे पशु-धन के क्षेत्र में कितने संपन्न हैं। ये आंकडे १९८१ के आधार पर दिये गये हैं।

	भारत	अर्जेंटिना	आस्ट्रिया	कोलंबिया	ब्राजील
गाय-बैल	२७८	२०८९	१३६५	९१७	७२८

	भारत	नेपाल	पाकिस्तान	थायलैंड	वियतनाम
भैंस	१००.	२८४	१३०	१२५	४०३

	भारत	सुडान	पाकिस्तान	इथोपिया	टर्की	सोमानिया
बकरे	११८	६७७	३८७	५२३	३९८	३२६४

	भारत	न्यूजीलैंड	अर्जेंटिना	उरूगवे	आस्ट्रेलिया	द. अफ्रीका
भेड	६२	२३५२८	१०८३	७८७९	७६७१	१०२२

आज तो सन् १९८९ में मुझे, मेरे देश में कहीं भी दस व्यक्तियों के पीछे दो गाय-बैल तथा एक भैंस दिखायी नहीं देती !

संस्कृति नष्ट होने पर स्वराज का कोई अर्थ नहीं

जनता को चाहिये शुद्ध, सात्विक, स्वादिष्ट अन्न और वह मिल सकता है – पशुखाद से। जनताको मिलता है जहरीला, निकृष्ट अन्न, और यह मिलता हैं – रासायनिक खाद्य से व पेस्टीसाईड से।

जल, वायु-मिट्टी की रक्षा करता है गोबर। गोबर के लिये चाहिए पशु-रक्षा।

पशु हत्या से – मनुष्य-हत्या, आखिर देश की हत्या !
आपको क्या चाहिये ?

केशरीचंद मेहता
महामंत्री

अ. भा. कृषि गोसेवा संघ
गोपुरी, वर्धा

जनस्वास्थ्य पर कीटनाशकों का प्रकोप

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार विश्व भर प्रतिवर्ष तीस लाख टन कीटनाशक का प्रयोग होता है।

कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कीटनाशकों का इस्तेमाल खतरनाक दर से बढ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक दशक के बाद कीट फफूंद और खरपतवार-नाशकों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खपत दो गुनी हो जाती है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कीटनाशकों के प्रयोग से होनेवाली कृषि और जनस्वास्थ्य संबंधी हानि की भरपाई पर १९७७ में २.७ अरब डालर का खर्च आया जो १९८० में बढकर ११.६ अरब डालर हो गया। अनुमान है कि १९९० में यह १८. ५ अरब डालर हो जायेगा।

रिपोर्ट की चेतावनी है कि कीटनाशकों के बढते इस्तेमाल की सबसे बडी कीमत मानव जीवन और पर्यावरण पर इसके हानिकारक प्रभाव के रूप में चुकानी पडती है। इस प्रवृत्ति का एक और गंभीर खतरा यह विकसित हो रहा है कि कीडे-मकोडों में कीटनाशकों के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास।

रिपोर्ट के अनुसार जैसे-जैसे कीडों में प्रतिरोध की क्षमता विकसित होती जाती है वैसे-वैसे कीटनाशकों की मात्रा बढती जाती है।

विश्व खाद्य संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा गठित समन्वित कीट नियंत्रण पर विशेषज्ञों के पैनल का आकलन है कि कीटों की करीब ५०० प्रजातियां एक अथवा कीटनाशकों के विरुद्ध प्रतिरोधी हो चुकी हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तरी अमरीका में १९५० से १९७० के दौरान कीटनाशकों के प्रयोग में बारह गुनी वृद्धि हुई और इस कारण इस अवधि के दौरान फसल में हानि दो गुनी हो गयी विकासशील देशों में स्थिति और भी बदतर है। कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रवृत्ति से सबसे अधिक नुकसान जन-स्वास्थ्य पर पडता है।

रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया के वेक्टर नामक मच्छरों में डॉट सहित विश्वभर में सबसे अधिक इस्तेमाल में लाये जाने वाली कीडेमार दवाइयों के

विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित हो गयी है। इसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष कम से कम दस करोड लोग मलेरिया की चपेट में आते हैं, जिनमें से बीस लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। कार्यक्रम के अनुसार प्रतिवर्ष दस लाख लोग कीटनाशकों के जहर की चपेट में आते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पडता है। कनाडा जैसे विकसित देशों में दस प्रतिशत किसान और खेतिहर मजदूर कीटनाशकों के जहर से प्रभावित पाये गये।

(दैनिक 'नवभारत' नागपुर से)

४७ गायें बचाई गई

वध हेतु ले जाई जा रही ४७ गायें मंदसौर के नाके पर पकड में आयी। यहां के गोरक्षा-कार्यकर्ताओं को ज्ञात हुआ कि ट्रक में गायें भर कर जा रही हैं तो उन्होंने पीछा किया, पर ट्रक तेजी से भागी। यहां पुलिस से संपर्क किया, तुरंत वायरलेस हुआ और ट्रक पकड ली गई।

इस ट्रक में डबल पार्टिशन में ४७ गायें क्रूरतापूर्वक ठूंस-ठूंस कर भरी थी। ऊपर भरी गायों के चारों पैर बंधे हुए थे। ट्रक चारों ओर से पेक थी। पुलिस ने जब गाडी रोकी तो अंदर बैठे मालिक और रखवाले भाग निकले। मात्र एक व्यक्ति ही पकडा जा सका। पुलिस ने मध्य प्रदेश पशु-परिरक्षण अधिनियम में प्रकरण बनाकर प्रस्तुत किया। ट्रक जमानत पर छूट गया। गायें मंदसौर के देहात थाने पर भूखी-प्यासी खडी हैं। कसाइयों ने कुछ भूसा डाला है। नीमच के कार्यकर्त्ताओं ने गायों की अस्थाई कस्टडी की मांग की है।

उल्लेखनीय है कि यह ट्रक अवैध रूप से कत्ल हेतु गायों के परिवहन हेतु ही लगी हुई है। अ. भा. कृषि गोसेवा संघ के महामंत्री श्री केशरीचन्द मेहता ने बताया कि मन्दसौर जिले की १५ ट्रकें पिछले सप्ताह महाराष्ट्र में पकडी गई, जिन पर अपराधिक प्रकरण कायम हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि म. प्र. से हजारों गोवंश महाराष्ट्र के कत्लखाने में जा रहा है। विशेषतः बकराईद के लिये हजारों छोटे-छोटे बछडा-बछडे उधर एकत्र किये जा रहे हैं।

("नई विधा" १८ जून ९० से)

Be Vegetarian, Have Healthy Long Life

Poultry Industry claims being fifth in the world with its production capacity of 22,880 million eggs which was almost nil in 1970s and so it demanded a Board with a grant of Rs. 650 crores but feel sorry that its proposal for the Board and funds has been rejected by the Govt & that too when it feels that even if the consumption per capita of egg which is 24 eggs p. a can be increased by one egg, it can provided employment to 35,000 people and thus with increasing egg consumption can eliminate unemployment.

I however congratulate the Govt for rejecting the grant to the Industry since poultry is not farming as being claimed or propogated as eggs don't grow on ground like vegetables, they are the products of birds and these birds are forced to lay eggs bearing all inhumane, painful, cruel tortures, naturally against the ethics and moral values which Indians have inherited from their forefathers.

Again providing employment or employment opportunities just can't be a ground for grant, when Eggs are a carrier for several diseases like Heart failure, kidney problem & blood pressure etc, naturally human health can't be sacrificed in the name of employment, as it has not been sacrificed in the case of drug trafficking. The right of healthy survival of a citizen is the prime duty of democratic law and so it is the duty of the Govt to protect them from health hazards. It is mere misleading propaganda that eggs help in better health, which is untrue.

100 gm egg contains as much as 550 miligram Cholesterol and it is a fact that high choles- terol diet carries high risk of coronery artery disease, stroke, kidney

failure etc. It is so only Diet experts don't advise eggs at all, to those having persistent high cholesterol level. Even people with normal cholesterol level are being warned since it carries risk of developing high cholesterol. The University of Minnesota School of public health after study on 12,000 people in Finland, Greece, Netherland, Japan, Italy, USA & Yugoslavia has come to the truth about its bad impact on human health.

Another study made by Dr. MC Marmot at Univetsity of California, Berkley, of heart disease rates of people of Japan who lived in different parts of the world. The results demonstrated an exact statistical correlation for all groups between consumption of saturated fat and cholesterol and death due to coronary heart disease.

Further more, at the University of IOWA, Dr. Mark Armstrong and his colleagues fed a group of monkeys a diet rich in egg yolk, one of the leading suppliers of saturated fat & cholesterol in the American diet. The coronary arteries of these monkeys rapidly became encrusted and atherosclerosed demonstrated by cine angiography. These monkeys were then put on diet devoid of cholesterol and a repeat study done after 18 months showed remarkable change in atherosclerosis.

I would like to quote another large study conducted at Lome Linda University at California, which involved 24,000 people. The results are reported in American Journal of Clinical Nutrition. This study found that the heart disease mortality rate was 10 times more among people who were eating eggs compared to vegans.

The study conducted by Harvard School of Public health by Dr. Mark Hegstead reveals that each 100 mg of egg yolk cholesterol raised blood cholesterol level in adult men

an average of 4 to 5 mg. Another study done at the University of Minnesota found that a diet with 300 mg of egg cholesterol per day caused an average blood cholesterol level of 16 mg higher than a diet with only 50 mg cholesterol.

It is so only experts say, 'In regions where eggs & meat are scarce, cardiovascular diseases are unknown'.

In our country the scope of innumerable diseases through eggs is enormous due to unhygenic mode of handling eggs in poultry Industry, as well in their transport, it is so only more than 20% broiler units are unable to operate economically, since the spread of diseases to broilers are enormous, one need not be surprised, if for economic greediness eggs containing diseased bacteria, find way to feed poverty riddens, who may be tempted to buy cheap or are forced to overlook the quality.

It is well known that Eggs shell has more than 15,000 pores, through which micro organisms make free entry and often infect the embryo, egg yolk again is good media for bacterial growth. The common bacterias are salmonella, shiegella & staphylococci and these bacterias are known for out break of acute gastroentertis and thousands of deaths every year in our country due to such epidemic is no secret.

I conclude, eggs are neither a better source of vitamin nor to our cultural heritage rather pulses, wheat, vegetables are rich in vitamins and economic too and again suits our cultural heritage.

I suggest, "BE VEGETARIAN, HAVE HEALTHY LONG LIFE"

16, India Exchange Place
Calcutta – 700001

PANNALALL MUNDHRA

Ministery of Agriculture
Krishi Bhavan,
New Delhi-110 001.

Dear Sir,

Dr. k. k. Agarwal, Vice Chairman of Heart Care Foundation of India has made a very important statement :

> "Artificial fertilisers, a frequent input of the present day cultivation, also added to free radicals and were harmful to heart. Unlike natural manure, they did not provide protection against high cholesterol and environment pollution."

Dr. H. H. Kauf, the noted Soil Chemist has said :

> "Modern agriculture can honestly claim only two notable crops - dieases and pests – to these we can now add third - poison, in the form of nitrates and nitrites."

Encyclopaedia Britannica, 1979, Edition, Vol. 19, page 648 mention :

> "The contamination by communal and industrial waste and by agricultural fertilisers is a serious threat for the Earth's entire hydrographic system and the very existence of human society."

The ill effects of chemical fertilisers on land productivity can be seen from ICAR Report for 1988-89 at page 86, which makes a mention that generally the farmers apply only nitrogen and experiments made over a period of 5 years have shown the loss of productivity at 4 different Centres as below.

Palampur	96-98%	Jabalpur	58–63%
Ranchi	81–84%	Bhubaneswar	32–34%

The Department has also recommended use of 10-15 tonnes of compost.

The subsidy given for chemical fertilisers according to your own statement in parliament was as below :

For 1989-90	Rs. 46 arab, 1 crore
For 1988-89	Rs. 32 arab.

Alas, there is no policy, no support for use of compost inspite of serious ill-effects of chemicai fertilisers as being reporte by different authorities, a sample of which has been quoted in this letter. We, therefore, suggest the subsidy on fertiliser be done away with over a period of 3 years and 25% of the funds so saved be allotted for organic farming.

Bharat Gosewak Samaj
C-38, Pamposh colony
New Delhi- 110 048

Cordially,
Laxmi Narain Modi
Chairman

सवाई माधोपुर में मानवमुनि का अभिनंदन

अ. भा. योगप्रचार के तत्वावधान में सवाई माधोपुर विशुद्धानगर योगाश्रम में श्री. मानवमुनि का अभिनंदन समारोह का आयोजन राष्ट्रीय संत योगाचार्य स्वामी श्री. भास्करानंदजी परमहंस की अध्यक्षता में किया गया। प्रमुख अतिथि वडोदरा निवासी संत स्वामी श्री. रामप्रसादजी रामस्नेही एवम् डॉ. मोहनलालजी हरियाना, श्री. शामजी भीखा दिल्ली, श्री. गोवर्धन-लालजी, स्वामी श्री. कृष्णवदन गोस्वामी वृन्दावन आदि अनेक विद्वानोंने 'मानव मानव से करें, प्रेम करें' इस आशयके विचार प्रगट किये।

स्वामी श्री. भास्करानंदजी परमहंस ने मानवमुनि को शाल ओढाकर अभिनंदन-पत्र भेंट किया।

अभिनंदन का उत्तर देते हुए कहा कि यह सब मैं महापुरुषों के चरणों में समर्पित करता हूं। और देश में चल रही मानव हिंसा और पशुहिंसा के प्रति दुःख दर्द प्रगट करते हुए, उसे मिटाने के लिए जुट जाने की उपस्थितों से प्रार्थना की।

गोवंश-हत्या बंदी समाचार

मकसी धर्मपाल किसान गोरक्षा सम्मेलन

२२ जुलाई ९० को श्री. धर्मपाल, महावीर नवयुवक मंडल मकसी (मध्यप्रदेश) के तत्वावधान में किसान गोरक्षा सम्मेलन का आयोजन विक्रमदास सलाहकार श्री पी. सी. चोपडा रतलाम की अध्यक्षता, में हुआ। प्रमुख अतिथि श्री. मानव मुनि थे। धर्मपाल किसान मजदूरों, किसानों को व्यसनमुक्त होकर, शाकाहारी बनने का संदेश दिया गया। गोवंश-हत्या बंदी केंद्रिय कानून की मांग की गई।

आंध्र सरकार वरंगल मार्ग पर हैदराबाद शहर से बीस किलोमीटर दूरी पर ११ करोड रुपये खर्च करके हर रोज ४००० भेड-बकरियां और ४०० गायों-भैंसों का कतलखाना खोल रही है। उसको तुरंत रोकने का प्रस्ताव पास किया गया।

आंध्र प्रदेश सरकार (१) अत्याधुनिक कतलखाना, (२) संसाधितखाद्य इकाई, (३) खरगोश और बटेर की खेती मांसाहार के हेतु खडा कर रही है, इसका भी विरोध श्री मानव मुनिजी ने किया।

श्री. पार्श्वनाथ निर्वाण महोत्सव पर हुए अहिंसा-संमेलन में आचार्य १०८ श्री. सन्मति सागरजी ने २८ जुलाई ९० को हुए सम्मेलन में गोवंश-हत्या बंदी पर जनता और सरकार से पुरजोर अपील की। बालाचार्य श्री. योगेन्द्र सागरजी ने भी प्रधान मंत्री को जगह-जगह से प्रस्ताव भेजने की अपील की।

वध हेतु जा रहे हजारों पशु बरामद

योगीराज देवरहा बाबा सेवा समिति के माध्यम से चलाये जा रहे गोवंश-बचाव अभियान के तहत देवरिया जिले के थाना पटहेरवा, तरया सुजान के थानाध्यक्षों ने पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री. हिम्मत सिंह के निर्देश पर

हजारों गाय-बैलों एवम् बछडों को छुडाने के लिये २७ पशु-व्यापारियों को गिरफ्तार करके २७ ट्रकें जप्त की ।

सेवा समिति के संयोजक श्री अभयानंद द्विवेदी ने पत्रकारों को तथा गोरक्षकों को बतलाया कि थानाध्यक्ष पटहेरवा श्री. प्रेमसिंह बिस्ट नं १२ ट्रकों पर ले जा रहे सैंकडों बैल, कुछ गायों और बछडों को बरामद किया और मुकदमा दर्ज किया, जबकि थानाध्यक्ष तरया सुजान ने २७ मई को १४ ट्रकों पर से ५४४ बछडों सहित २७ तस्करों को हिरासत में लिया ।

थानाध्यक्ष तुर्क पट्टी के श्री. चन्द्रमोहन श्रीवास्तव ने ३ ट्रकों पर ले जा रहे सैंकडों गोवंश को छुडाकर ड्रायवर सहित ४ वेपारियों को बन्दी बना लिया। थाना बखिरा की पुलिस ने वध हेतु जा रहे १६० पशुओं सहित ४ वंजारों को जेल भेज दिया ।

बखिरा, दुधारा एवं दुर्ग ज्योत क्षेत्र के कई गांवों में गोवध होता है, १७ क्विटल मांस के साथ और सैंकडों पशुओं के साथ कई कसाई पकडे गये । बस्ती के गोरक्षकों ने काफी सक्रियता दिखाई । १३ बछडों को कतल करने की अवस्था में खड्डा पुलिस ने ३ पशुव्यापारियों को गिरफ्तार किया ।

एक नेता ने थानाध्यक्षों पर दबाव डालकर या लालच दिखाकर उन्हें इस कारंवाई से विरत करने का प्रयास किया । लेकिन पुलिस-अधीक्षक श्री. सिंह के कुशल निर्देशन के चलते उन नेताओं की चाल विफल रही । ज्ञातव्य है कि सेवा समिति द्वारा राजकीय मार्ग नदियों के घाटों पर देवरहा बाबा के आशीर्वादस्वरूप संयोजन श्री. द्विवेदी कर रहे हैं ।

★ ★

मेरे विचार से गोरक्षा का प्रश्न स्वराज्य के प्रश्न से छोटा नहीं । कई बातों में मैं इसे स्वराज्य के प्रश्न से भी बडा मानता हूं । जब तक हम गाय को बचाने का उपाय ढूंढ नहीं निकालते तब तक स्वराज्य अर्थहीन कहा जायगा ।

– गांधीजी

आम की पैदावार में भारत का पहला स्थान

आमों की पैदावार के क्षेत्र में भारत का विश्व में पहला स्थान है, लेकिन आमों के निर्यात में उसका स्थान चौथा है।

आम के निर्यात के मामले में फिलीपीन्स का पहला स्थान है, लेकिन पैदावार में उसका पाचवां स्थान है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उप-महानिदेशक के. एल. चड्ढा ने कहा कि भारत उत्तम किस्म के तथा थोड़े से प्रयास से विश्व बाजार में आम के निर्यात के क्षत्र में एकाधिकार स्थापित कर सकता है।

उन्होंने कहा कि भारतीय बागवानी विज्ञानी आम के पेड की एक ऐसी बौनी प्रजाति विकसित करने में लगे हैं जिसके सभी फलों का आकार एक समान हो। देश के अनेक राष्ट्रीय कृषि संस्थानों में इसके लिए अनुसंधान किए जा रहे हैं। एक समान आकार के आमों वाले वृक्षों की जरूरत इसीलिए महसूस की गई कि आम निर्यात के क्षेत्र में भारत अग्रणी बन सके। भारत की गिनती सबसे बडे तथा सबसे उत्तम किस्म के आम निर्यात करने वाले देशों में है।

भारत में एक अरब छह करोड तीस लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आम की फसल होती है तथा इसका वार्षिक उत्पादन करीब नौ अरब ३३ करोड टन है, जो विश्व-उत्पादन का ७० प्रतिशत है। भारत आम के कुल उत्पादन का केवल ०.०२ प्रतिशत ही निर्यात करता है। वर्ष १९८७-८८ में इससे उसे १७.३ करोड रुपये की आय हुई थी। समान आकार के आम निर्यात बाजार की एक आवश्यकता है। महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के केवल अल्फांसों किस्म के आमों में ही यह विशेषता पाई जाती है।

गाय का दूध है दवा, गोश्त है बीमारी

अल्लाह ने नहीं उतारी कोई बीमारी, जिसकी उसने दवा नहीं उतारी, सिवाय बुढापा और मौत के। तुम गाय का दूध पीने का पावन्द हो जाओ। गाय के दूध के अन्दर सभी तरह के पौधों का सत्व है।

गाय का दूध हमेशा पीयो, वह दवा है। उसका घी बीमारी दूर करता है। उसके गोश्त से बचो, चूंकि उसका गोश्त बीमारी है।

— हजरत मुहम्मद पैगम्बर

गोरक्षा पर महात्मा गांधी के विचार

मेरे विचार से गोवध और मनुष्यवध, दोनों एक ही वस्तु हैं। इन दोनों को रोकने के लिये यही उपाय है कि हम अहिंसा की शिक्षा का प्रचार करें, मारनेवाले को प्रेम से अपना लें। प्रेम की परीक्षा तपश्चर्या में है। तपश्चर्या में है। तपश्चर्या अर्थात् दुःख सहन करना। मैं मुसलमानों के लिये जितने अंश में दुःख सहन हो, उतने अंश में दुःख सहन करने के लिये तैयार हो गया, इसका कारण स्वराज्य की प्राप्ति, यह छोटी बात तो थी ही, परन्तु गाय के बचाने की बडी बात भी उसमें थी। मेरी समझ के अनुसार कुरान शरीफ में यह लिखा है कि किसी भी प्राणी का नाहक प्राण लेना पाप है। मुसलमानों को यह समझाने की शक्ति प्राप्त करने की मैं इच्छा करता हूं कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ रहकर गोवध करना हिंदुओं का खून करने के बराबर है; क्योंकि कुरान कहता है कि खुदा ने, निर्दोष पडोसी का खून करनेवाले के लिये जन्नत नहीं है, ऐसा निश्चय किया है। इसीलिये आज मैं मुसलमानों का साथ देता हूं, उनको दुःख न हो ऐसा वर्ताव करता हूं, उनकी खुशामद करता हूं और यह इसलिये कि इस उपाय से उनकी धर्मवृत्ति जाग्रत् हो।

ऋषियों ने कहा है कि गो-रक्षा हिंदू का परम कर्त्तव्य है, क्योंकि उससे मोक्ष मिलता है। मैं नहीं मानता कि केवल स्थूल गाय की रक्षा करने से मोक्ष मिल जाता है, क्योंकि मोक्ष पाने के लिये तो राग-द्वेष छोडना जरूरी है। इसलिये गोरक्षा का हम जो सामान्य अर्थ करते हैं, उनसे विशाल अर्थ होना चाहिये। यदि गोरक्षा से मुक्ति मिलती हो तो गोरक्षा केवल गाय की रक्षा नहीं, बल्कि प्राणिमात्र की रक्षा होनी चाहिये। मतलब यह है कि चाहे जिसकी हिंसा से, कटु वाक्य से स्त्री-भाई-बन्धु को मनमाना दुःख देना, जिस किसी प्राणी को दुःख देना, यह गोरक्षा-धर्म का उल्लंघन है। हिंदू धर्म में गाय की रक्षा का उपदेश है, इसका अर्थ क्या यही है कि गाय को न मारना और बकरी को मारना? अथवा गाय को बचाने में मुसलमान को मारना? गाय का संकुचित अर्थ करने से ऐसे बहुत से अनर्थ सम्भव हैं। गोरक्षा करनेवाले बहुतेरे हिंदू दूसरे प्राणियों का मांस खाते हैं। वे गोरक्षा का दावा नहीं कर सकते, यह बात मेरी अल्पमति में आती है।

जरूरतें पूरी करके नहीं, शक्ति जगाकर

जनता के बीच जाओ
जनता के बीच रहो
उनसे सिखो
उनके साथ बैठकर योजना वनावो
काम करो उनके साथ
उनकी जानकारी से प्रारंभ करो
वताकर सिखावो, और करके सिखो
केवल नमूना नहीं, रचना चाहिए
टुकडों के पैवंद नहीं
एकसंध व्यवस्था चाहिए
जरूरतें पूरी करवा के नहीं, शक्ति जगाकर
वताकर सिखावो एवं करते-करते सिखो
केवल नमूना नहीं, रचना चाहिए
टुकडों के पैवंद नहीं,
एकात्मिक दृष्टि चाहिए ।
जरूरतें पूरी करके नहीं, शक्ति जगाकर -

[ग्रामीण पुनर्रचना के क्षेत्र के पथदर्शी क्रांतिकारक डॉ. जेम्स येन द्वारा ग्रामीण विकास में लगे कार्यकर्ताओं के लिए संदेश]



रजि नं. **WDA 86** विना टिकट भेजने का परवाना नं. 8

अ. भा. कृषि गो-सेवा संघ, दिल्ली कार्यालय

क्षेत्रीय कार्यालय :

श्री. हरिकिसनजी गुप्ता, अध्यक्ष
कृषि गो-सेवा संघ दिल्ली क्षेत्र,
14 प्रताप चेंबर, गुरुद्वारा रोड,
करोलबाग, नई दिल्ली – 110005
फोन : 588057, 5733931, 7128147

सुप्रीम कोर्ट संपर्क कार्यालय :

श्री. केशरीचंदजी मेहता, महामंत्री
अ. भा. कृषि गो-सेवा संघ,
श्री. जस्टीस. गुमानमलजी लोढा, सांसद
C. 1/15 पंडारा पार्क, पंडारा रोड
नई दिल्ली – 110003
फोन : 384671, 388125

प्रिन्टेड मैटर

27· मुमुक्षु [illegible] स्तकालय और वाचनालय,
अस्सी, [illegible] णसी-221 005.
(उत्तर प्रदेश)

प्रेषक : 'गोरास' गोपुरी, वर्धा (महाराष्ट्र)